● वर्ष-2
● अंक-255
रायपुर, शुक्रवार 16 जून 2023
● पृष्ठ-6
● मूल्य-3 रु.

।। संगच्छध्वम् संवदध्वम् ।।

समाचार पचीसा

राजनीति का जनपक्षकार

samacharpacheesa@gmail.com

समान नागरिक संहिता की सुगबुगाहट तेज

कई सामाजिक बुराइयां धार्मिक रीति-रिवाजों के रूप में शह ले लेती है; विधि आयोग ने दी थी चेतावनी

नई दिल्ली। इस साल के आखिरी तक पांच राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं। अगले साल लोकसभा चुनाव है। इस बीच, देश में एक बार फिर से यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी समान नागरिक संहिता (ष्टष्ट) लागू करने की सुगबुगाहट तेज हो गई है। सरकार की ओर से गठित 22वें विधि आयोग ने समान नागरिक संहिता पर आम जनता और धार्मिक संस्थाओं के प्रमुखों से विचार विमर्श और राय मांगने का कार्य शुरू कर दिया है। इस बीच, पिछले विधि आयोग की एक चेतावनी पर फिर से चर्चा शुरू हो गई है। दरअसल पांच साल पहले, विधि आयोग ने कहा था कि सती प्रथा, बाल विवाह और तीन तलाक जैसी कई सामाजिक बुराइयों धार्मिक रीति-रिवाजों के रूप में जन्म लेती हैं। धर्म के रूप नें कानून के तहत उनकी सुरक्षा की मांग करना गंभीर मूर्खता होगी।

गौरतलब है कि 21वें विधि आयोग द्वारा अगस्त, 2018 में जारी %पारिवारिक कानून में सुधार% पर एक परामर्श पत्र भी जारी किया गया था। जिसमें ये तर्क दिए गए थे। अब वर्तमान विधि आयोग ने नए सिरे से इस मुद्दे पर विचार-विमर्श की प्रक्रिया शुरू की है। 22वें विधि आयोग ने एक सार्वजनिक सूचना में कहा है कि चूंकि इस विषय की प्रासंगिकता और महत्व साथ ही विभिन्न अदालती आदेशों को ध्यान में रखते हुए पिछले परामर्श पत्र को जारी किए तीन साल से अधिक समय बीत चुका है। ऐसे में 22वें विधि आयोग ने इस विषय पर नए सिरे से विचार-विमर्श करना उचित समझा।

2018 में जारी परामर्श पत्र में कहा गया था कि धर्म की स्वतंत्रता और धर्म के सिर्फ पालन ही नहीं,

बल्कि प्रचार करने के अधिकार को एक धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्र में संरक्षित किया जाना चाहिए। इसमें यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि कई सामाजिक बुराइयां धार्मिक रीति-रिवाजों के रूप में शरण ले लेती हैं। इसमें सती, गुलामी, देवदासी, दहेज, तीन तलाक, बाल विवाह या अन्य प्रथाएं और बुराइयां हो सकती हैं। ऐसे में %धर्म% के रूप में कानून के तहत उनकी सुरक्षा की मांग करना एक गंभीर मूर्खता होगी।

परामर्श पत्र में कहा गया था कि ये प्रथाएं मानवाधिकारों के बुनियादी सिद्धांतों के अनुरूप नहीं हैं। साथ ही किसी भी धर्म के लिए ये आवश्यक हैं। धर्म के लिए आवश्यक होने पर भी किसी प्रथा को जारी रखने का कारण नहीं होना चाहिए, अगर यह भेदभावपूर्ण है।

समान नागरिक संहिता

संविधान में समान नागरिक संहिता यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड एक ऐसा प्रावधान होगा, जिसमें सभी नागरिकों के लिए एक समान कानून होंगे। फिर वह किसी धर्म, जाति या समुदाय से क्यों न हो। इसमें शादी, तलाक, गोद लेने की प्रक्रिया और संपत्ति के बंटवारे में सभी धर्मों के लिए एक ही कानून लागू होगा।

समान नागरिक संहिता एक पंथनिरपेक्ष कानून होता है जो सभी धर्मों के लोगों के लिए समान रूप से लागू होता है। इसके जरिए हर मजहब के लिए एक जैसा कानून आ जाएगा। अभी अलग-अलग धर्मों के लिए अलग-अलग पर्सनल लॉ हैं, जो समान नागरिक संहिता लागू होने के बाद खत्म हो जाएंगे। इसमें महिलाओं और पुरुषों को भी समान अधिकार मिलेंगे। मुस्लिम, ईसाई और पारसी समुदाय का पर्सनल लॉ है जबकि हिन्दू सिविल कोड के तहत हिन्दू, सिख, जैन और बौद्ध आते हैं।

इससे पहले, 21वें विधि आयोग ने इस मुद्दे का परीक्षण किया था। आयोग ने दो मौकों पर सभी पक्षों के विचार मांगे थे। 21वें विधि आयोग का कार्यकाल अगस्त 2018 में समाप्त हो गया था। इसके बाद, 2018 में 'पारिवारिक कानून में सुधार' पर एक परामर्श पत्र जारी किया गया था। तब से अब तक तीन साल हो चुके हैं। ऐसे में सरकार ने नए सिरे से इसपर काम करना शुरू कर दिया है। इसी के तहत बड़े पैमाने पर लोगों और धार्मिक संगठनों के विचार लिए जा रहे हैं। इसके पहले करीब कई दौर की बैठकों के बाद विधि आयोग ने ष्टष्ट पर वितृत रिपोर्ट तैयार की है। इसी के आधार पर केंद्र सरकार ष्टष्ट बिल तैयार करेगी।

यूं तो समान नागरिक संहिता को पूरे देश में लागू करने की तैयारी है। हालांकि, उत्तराखंड, गुजरात, मध्य प्रदेश, असम जैसे भाजपा शासित राज्यों में इसको लेकर कमेटी का गठन हो चुका है। ये कमेटी अलग-अलग धर्म, समुदाय और विशेषज्ञों से इस बारे में राय ले रही है। इसी आधार पर इसको लेकर कानून तैयार किया जाएगा। बताया जाता है कि सरकार पहले इसे राज्यों में लागू करना चाहती है। अकेले उत्तराखंड में इस मामले में करीब ढाई लाख सुझाव मिले थे। इसका कमेटी ने अध्ययन कर लिया है। इसके अलावा करीब-करीब सभी हितधारकों से संवाद के बाद कमेटी रिपोर्ट को अंतिम रूप देने के लिए बैठकें कर रही हैं। उम्मीद जताई जा रही है कि कमेटी जल्द ही रिपोर्ट पेश कर देगी।

विफलताओं से ध्यान हटाने के लिए- कांग्रेस

कांग्रेस ने समान नागरिक संहिता (यूसीसी) को लेकर केंद्र सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि विधि आयोग के यूसीसी पर फिर से जनता की राय लेने के फैसले से साफ होता है कि नरेंद्र मोदी सरकार अपनी विफलताओं से ध्यान हटाने के लिए लिए अपने पुराने एजेंडा को अपना रहा है। कांग्रेस सचिव (संचार) जयराम रमेश ने कहा कि यह अजीब है कि विधि आयोग फिर से राय मांग रहा है। विधि आयोग ने इसे लेकर कोई कारण नहीं दिया है। रमेश ने आगे पूछा कि आयोग जरूरी मामलों को छोड़कर फिर से इस विषय पर क्यों विचार कर रहा है? उन्होंने कहा कि वास्तविक कारण यह है कि 21वें विधि आयोग ने इस विषय की विस्तृत और व्यापक समीक्षा करने के बाद यह पाया कि समान नागरिक संहिता इस स्तर पर न तो आवश्यक है और न ही वांछनीय है। उन्होंने कहा कि फिर से उसी मुद्दे को उठाना यह उनके पुराने एजेंडे को दर्शाता है। सरकार ने अपनी विफलताओं को छिपाने के लिए यही पैंतरा आजमाया है।

इन दिनों

✍ अजय सेतिया

तमाम विरोधियों के लिए मोदी का जवाब

लोकसभा चुनाव में अभी ग्यारह महीने बाकी हैं। लेकिन दोनों तरफ से तीरंदाजी शुरू हो गई है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाईडेन भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से चाहे जितनी गलबहियां करें, यह बात किसी से छिपी नहीं कि रूस यूक्रेन युद्ध में भारत की भूमिका से अमेरिका और जर्मनी मोदी से बेहद खफा हैं। इसके प्रमाण अब मिलने शुरू हो गए हैं। राहुल गांधी की व्हाईट हाउस में सीक्रेट मीटिंग हुई है। ट्विटर के पूर्व मालिक जैक डोर्सी का मोदी सरकार विरोधी बयान आ गया है। उनसे राहुल गांधी की मुलाक़ात के फोटो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। अरबपति जार्ज सोरोस का पहले ही बयान आ चुका है कि वह मोदी सरकार को हटाने के लिए सौ करोड़ डॉलर खर्च करेंगे। जार्ज सोरोस ने राहुल गांधी से बात करने के लिए उनकी भारत जोड़ो यात्रा में अपना प्रतिनिधि भेजा था। मोदी विरोधी उनके खिलाफ विदेशों से लड़ाई लड़ रहे रहे हैं । विदेशी ताकतें राहुल गांधी को प्रोजेक्ट करने में लग गई हैं, इधर राहुल गांधी की तरफ से नीतीश कुमार सारे विपक्षी दलों को एकजुट करने की कोशिश कर रहे हैं। यानि चुनावों से ग्यारह महीने पहले विपक्ष ने मोर्चाबन्दी शुरू कर दी है। विपक्ष की पहली बैठक 23 जून को पटना में हो रही है। वैसे बैठक इमरजेंसी वाले दिन 25 जून को होती, तो अच्छा रहता। देश को पता चलता कि इमरजेंसी के खिलाफ जेल जाने वाले कौन कौन से नेता इमरजेंसी लगाने वालों के साथ खड़े हैं। सत्ता हथियाने के लिए कांग्रेस का हथियार अब वे ही नेता बन गए हैं, जो इमरजेंसी के खिलाफ जेल गए थे। अब वे ही लोग कांग्रेस के तरकश के तीर बन गए हैं। लेकिन मोदी के तरकश के तीर भाजपा का एजेंडा है। यह वही एजेंडा है जिसके कारण जनता पार्टी की सरकार टूटी थी। जम्मू कश्मीर का विभाजन करके मोदी सरकार ने चीन को भी चुनौती देने का काम किया है। इसलिए चीन भी मोदी को किसी न किसी तरह हटाना चाहता है। वह भी राहुल गांधी की मदद कर रहा है। भारत में मीडिया का एक वर्ग भी चीन के साथ खड़ा है। इसके बावजूद कि चीन ने सारे भारतीय पत्रकारों को बाहर निकाल दिया है। यहां तक कि पिछले सात दशक से चीन समर्थक बने रहे हिन्दू अखबार के रिपोर्टर को भी चीन से बाहर निकाल दिया गया है। कर्नाटक के चुनाव नतीजों ने भारत के मुसलमानों की दिशा तय कर दी है कि वे 2024 में एकजुट होकर राहुल गांधी के हाथ मजबूत करेंगे। कर्नाटक सरकार ने गौहत्या पर लगा प्रतिबन्ध हटाने की बात कह कर जनसंघ का पुराना एजेंडा जीवित कर दिया है। अब भारत के हिन्दू इन्तजार कर रहे हैं कि मोदी के तरकश में कौन सा नया तीर है। मोदी ने अपने तरकश से पहला तीर निकाल लिया है, 14 जून को उसे चल भी दिया। विपक्ष की 23 जून की मीटिंग का एजेंडा इसी तीर ने सेट कर दिया है। मोदी ने विपक्ष को अपने एजेंडे में उलझाना शुरू कर दिया है। और वह एजेंडा है कॉमन सिविल कोड, जिसे हिन्दी में समान नागरिक संहिता कहते हैं।

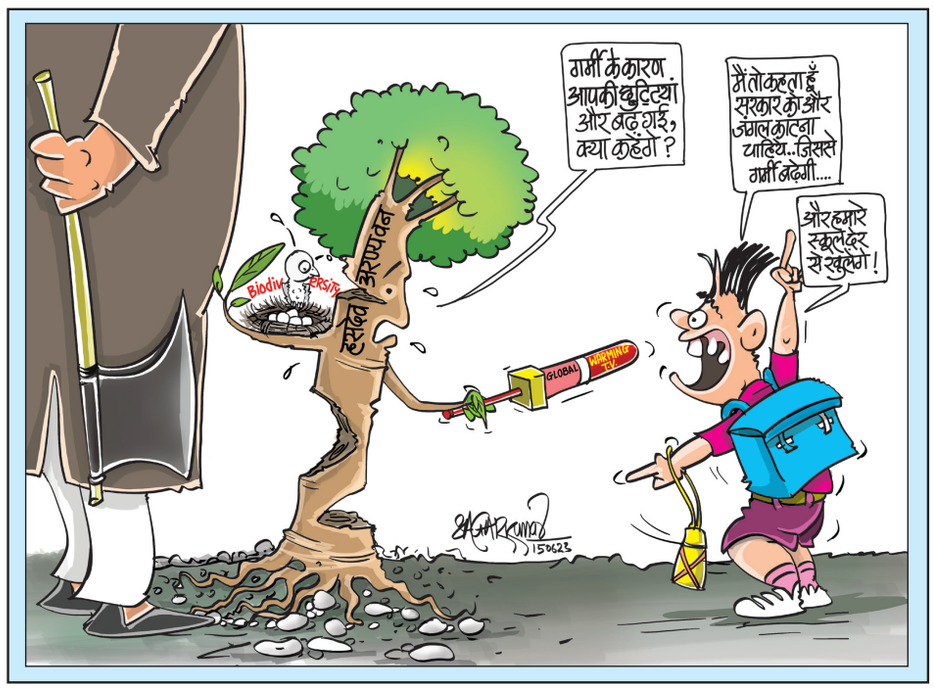

कर्नाटक में खत्म हुआ धर्मांतरण विरोधी कानून

बेंगलुरू। सिद्धारमैया के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार ने पिछली भाजपा सरकार द्वारा राज्य में पेश किए गए धर्म परिवर्तन के खिलाफ कानून को रद्द करने का फैसला किया है। राज्य के कानून और संसदीय मामलों के मंत्री एचके पाटिल ने कहा कि प्रस्ताव को आज राज्य कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है। इसे बदलने के लिए एक विधेयक बाद में सितंबर में राज्य विधानसभा में पेश किया गया था।

कैबिनेट ने स्कूली इतिहास की किताबों से केबी हेडगेवार के अध्यायों को हटाने का फैसला किया है, जो भाजपा के वैचारिक संरक्षक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संस्थापकों में से एक हैं। अध्याय पिछले साल जोड़ा गया था। साथ ही भाजपा सरकार द्वारा स्कूली पाठ्यक्रम में किए गए सभी बदलावों को भी उलट दिया गया है। पाटिल ने बैठक के बाद संवाददाताओं से कहा कि मंत्रिमंडल ने स्कूलों और कॉलेजों में भजन के साथ संविधान की प्रस्तावना को पढ़ना अनिवार्य करने का भी फैसला किया है। कैबिनेट ने कृषि बाजारों पर एक नया कानून लाने का भी फैसला किया है, जो भाजपा के सत्ता में रहने के दौरान बनाए गए कानून की जगह लेगा।

डॉ. हेडगेवार पाठ्यक्रम से बाहर

कर्नाटक सरकार ने डॉ. हेडगेवार को पाठ्यक्रम से हटा दिया है। हेडगेवार को हटाने के अलावा, राज्य सरकार ने स्कूलों और कॉलेजों में संविधान की प्रस्तावना और भजनों को पढ़ना अनिवार्य करने का भी फैसला किया है। इसके अलावा, कर्नाटक सरकार ने पुराने कानूनों को वापस लाने के लिए राज्य में ,क्कस्ट अधिनियम में

संशोधन करने का निर्णय लिया है। राज्य सरकार का ताजा कदम पिछली भाजपा सरकार द्वारा किए गए परिवर्तनों को संशोधित करने के लिए आया है।

शिक्षा मंत्री मधु बंगारप्पा ने कहा कि केबी हेडगेवार पर पाठ्यक्रम हटा दिया गया है ... उन्होंने (पिछली सरकार ने) पिछले साल जो भी बदलाव किए थे, हमने उन्हें बदल दिया है और पिछले साल से जो कुछ भी था उसे फिर से शुरू किया है।

हिंदुओं के खिलाफ है सिद्धरमैया सरकार-भाजपा

कर्नाटक के पूर्व शिक्षा मंत्री और भाजपा नेता बीसी नागेश ने कहा कि वे (कांग्रेस) मुसलमानों के वोट चाहते हैं, सिद्धरमैया की सरकार हिंदुओं के खिलाफ है ... वे हिजाब को फिर से पेश कर सकते हैं ... वे अल्पसंख्यकों के वोटों को आकर्षित करना चाहते हैं और हर चीज का राजनीतिकरण करना चाहते हैं। इससे पहले कर्नाटक के प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा मंत्री मधु बंगरप्पा ने कहा था कि विद्यार्थियों के हित में इसी साल ही स्कूली पाठ्यपुस्तकों की समीक्षा की जाएगी। उन्होंने कहा कि यह मामला शीघ्र ही मंत्रिमंडल के सामने उसकी मंजूरी के लिए रखा जाएगा।

प्रमुख समाचार

छत्तीसगढ़ के जनजातियों के दल ने राष्ट्रपति से की भेंट-मुलाकात

रायपुर। छत्तीसगढ़ के विभिन्न जिलों में निवासरत पांच विशेष पिछड़ी जनजातियों बैगा, पहाड़ी कोरवा, बिरहोर, कमार और अबूझमाड़िया के 80 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू से राष्ट्रपति भवन नई दिल्ली में जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा आयोजित विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समुदाय सम्मेलन में भेंट-मुलाकात की। राष्ट्रपति श्रीमती मुर्मू ने इस मौके पर छत्तीसगढ़ के सभी जनजाति समुदाय के लोगों से सीधा संवाद किया और उनकी संस्कृति, रीति-रिवाजों सहित सभी पहलुओं से रूबरू हुईं।

पंचायत चुनाव में हिंसा का हमारी पार्टी का लेना-देना नहीं: ममता

कोलकाता। पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनाव को लेकर राजनीतिक हलचल जारी है। राज्य में कई जगह हिंसक झड़पें भी देखने को मिली हैं। हिंसा को लेकर विपक्षी दल जबरदस्त तरीके राज्य की ममता

बनर्जी की सरकार पर हमलावर है। आज ममता ने साफ तौर पर कहा कि कुछ विपक्षी दल पंचायत चुनाव के नामांकन के दौरान गड़बड़ी पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं आज ही दक्षिण 24 परगना जिले के भांगर में तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) और इंडियन सेक्युलर फ्रंट (आईएसएफ) के कार्यकर्ताओं के बीच तनाव देखा गया। इलाके में बम फेंके गए, जिसके बाद पुलिस ने अनियंत्रित स्थिति को नियंत्रण में लाने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़े। नामांकन के दौरान हुई हिंसा की घटनाओं पर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इस पर अपना बयान दिया है। उन्होंने कहा कि इस्लामपुर और अन्य जगह जो समस्या हुई उसमें हमारी पार्टी की कोई भागीदारी नहीं है।

कोविन डेटा लीक मामले में तृणमूल ने दर्ज कराई शिकायत

कोलकाता। तृणमूल कांग्रेस के सांसद डेरेक ओ ब्रायन ने कोविन पोर्टल में संग्रहीत गोपनीय और संवेदनशील डेटा के लीक होने को लेकर मामला दर्ज कराया है। टीएमसी नेता ने दावा करते

हुए डेटा उल्लंघन को अभूतपूर्व स्थित बताते हुए कहा कि इसके अकल्पनीय परिणाम हो सकते हैं। कोलकाता के लालबाजार साइबर पुलिस स्टेशन में अपनी शिकायत में तृणमूल नेता ने कहा कि एक गहरी साजिश चल रही है जिसमें उच्च पदस्थ लोक सेवक, सरकारी अधिकारी और अन्य अज्ञात व्यक्ति शामिल हैं, जिन्होंने नागरिकों से संबंधित संवेदनशील डेटा लीक हुई है। टेलीग्राम पर कल के डेटा उल्लंघन के बारे में समाचार केवल इसकी बानगी भर है और इसकी जांच की जानी बाकी है कि इस तरह के डेटा को भारत के भीतर और साथ ही विदेशों में निजी संस्थाओं को कितनी दूर दिया गया।

उपद्रवियों ने इंफाल घाटी में कई घरों में आगजनी की

इंफाल। मणिपुर में हिंसा का दौर लगातार जारी है। उपद्रवियों ने आज इंफाल घाटी में कई घरों में आगजनी की। अधिकारियों ने बताया कि सुरक्षाबलों और उपद्रवियों के बीच झड़प के बाद मणिपुर के इंफाल शहर में आंसू गैस के गोले छोड़े गए। सेना और असम राइफल्स की इकाइयों ने विभिन्न स्थानों पर लगाए गए अवरोधों को हटाते हुए गश्त गतिविधियों में वृद्धि की है। स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है, हिंसा को शांत करने और शांतिपूर्ण वातावरण स्थापित करने के प्रयास चल रहे हैं। इस बीच, कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा कि हिंसा प्रभावित मणिपुर में स्थिति चिंताजनक है और उन्होंने भाजपा नीत केंद्र की आलोचना करते हुए कहा कि वह लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए तत्काल कदम नहीं उठा रही है। इससे पहले इंफाल पश्चिम जिले के लाम्फेल इलाके में बुधवार रात अज्ञात लोगों ने मणिपुर की महिला मंत्री नेमचा किपजेन के आधिकारिक आवास में आग लगा दी।

चीन सीमा से लगे सेक्टर में फोर्स की तैयारियों पर सेना की बैठक

लद्दाख। पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर तैनात शीर्ष सैन्य अधिकारी क्षेत्र में तैयारियों को और मजबूत करने के लिए परिचालन संबंधी चर्चा कर रहे हैं। यह बैठक गलवान घाटी संघर्ष की तीसरी वर्षगांठ पर आयोजित की जा रही है। 15 जून की रात को हुई झड़प में भारत ने चीनी सेना को भारी नुकसान पहुंचाते हुए अपने 20 सैनिकों को भी खो दिया था। कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी, 14 कॉर्प्स कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल रशीम बाली और वन स्ट्राइक कॉर्प्स कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल संजय मित्रा के साथ वहां तैनात अन्य फॉर्मेशन भी हैं। उत्तरी सेना कमान लद्दाख क्षेत्र का प्रभारी है और उसे मथुरा में मुख्यालय वाली वन स्ट्राइक कोर के रूप में एक नया गठन प्रदान किया गया है, जिसके तत्व देश के उत्तरी भागों में फैले हुए हैं। पूर्वी लद्दाख सेक्टर में अप्रैल-मई 2020 के चीनी आक्रमण के बाद सेना का पुनर्गठन सरकार और बलों द्वारा किया गया था। चीनी सेना के 50,000 से अधिक सैनिकों को 2020 के बाद से पूर्वी लद्दाख के विपरीत एलएसी पर तैनात किया गया है।

क्या फिर लौट आयी रामो वामो की राजनीति?

प्रदीप सिंह

नब्बे के दशक में भारत में जब चुनाव आयोग पारदर्शिता और निष्पक्षता का कीर्तिमान स्थापित कर रहा था तब भारत में एक नए तरह की राजनीति ने जन्म ले लिया था। यह राजनीति गठबंधन की थी, और गठबंधन के सामने कांग्रेस को हराने का लक्ष्य था। 1989 में कई क्षेत्रीय दलों का गठबंधन हुआ और उसका नाम राष्ट्रीय मोर्चा हुआ। वामपंथी दलों के गठबंधन का नाम वाममोर्चा था। इस तरह रामो-वामो ने मिलकर 1989 में कांग्रेस को सरकार बनाने से वंचित कर दिया था। पहले साठ के दशक में और फिर नब्बे के दशक में देश की राजनीति में गठबंधन की राजनीति का उदय हुआ। साठ के दशक में कई राज्यों में गठबंधन की सरकार बनी थी। उस गठबंधन में जनसंघ और सोशलिस्ट पार्टियां शामिल थी। तब कांग्रेस की तानाशाही से मुकाबला था। उस दौरान राजनीति में कुछ मुद्दों पर सहमति और कुछ मुद्दों पर दोस्ताना संघर्ष का फार्मूला निकाला गया। सरकार चलाने के लिए न्यूनतम साझा कार्यक्रम का मॉडल तय किया गया। यहां से राजनीति में वैचारिक समझौते का दौर शुरू होता है, जो आज तक जारी है।

गठबंधन की राजनीति से सबसे ज्यादा नुकसान वैचारिकता की राजनीति को हुआ। रातों रात राजनीतिक दलों और राजनेताओं की वैचारिक-राजनीतिक निष्ठा में बदलाव आया। दलबदल का दौर शुरू हुआ। राजनीति में विचार की कीमत मिट्टी के बराबर भी नहीं रह गयी। सारी राजनीतिक प्रतिबद्धता मंत्री बनने और मनचाहा विभाग पाने तक सिमट गई।

सरकार में शामिल होने के लिए कुछ कॉमन मुद्दों को खोज लिया जाता रहा। हालांकि इस दौर में देश की राजनीतिक परिघटना में सेकुलरवाद, राष्ट्रवाद और सामाजिक न्याय की राजनीति का भी उभार हुआ। अब राजनीति में आप इन तीन तत्वों में से किसी के पैरोकार हैं, तो बाकी किसी चीज की जरूरत नहीं थी। 2014 आते-आते राष्ट्रवाद की राजनीति ने सेकुलरवाद और सामाजिक न्याय की राजनीति की सीमारेखा तय कर दी। 2014 में नरेन्द्र मोदी की अगुवाई में भाजपा की प्रचंड जीत ने न सिर्फ राष्ट्रवाद को राजनीतिक विकल्प के रूप में स्थापित किया बल्कि गठबंधन की राजनीति को भी महत्वहीन कर दिया। अब जबकि राष्ट्रवाद के पूर्ण बहुमत वाली राजनीति के एक दशक पूरे होने जा रहे हैं तब एक बार फिर चर्चा तेज है कि 2024 के आमचुनाव में क्या होगा?

अमेरिका यात्रा के दौरान कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक सवाल का जवाब देते हुए कहा है कि केवल गठबंधन बनाकर भाजपा-एनडीए को नहीं हराया जा सकता है। इसके लिए एक विचार और विजन की जरूरत है। जिस समय राहुल गांधी अमेरिका में भाजपा को हराने के लिए विचार और विजन की आवश्यकता बता रहे थे, उसी समय बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार विपक्षी दलों की एकता के लिए गठबंधन की बैठक करने की कोशिश कर रहे थे। एक बार टल चुकी विपक्षी दलों की ये बैठक अब 23 जून को होने जा रही है। कई दल इसमें शामिल होंगे और कई दलों ने बैठक में शामिल होने से इंकार भी कर दिया है। बंगाल की तृणमूल कांग्रेस, राजद, जेडीयू, एनसीपी, डीएमके, आम आदमी पार्टी और उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना जैसी कई पार्टियां बैठक में शामिल हो रही हैं। लेकिन बीजू जनता, बीआरएस, टीडीपी, बसपा जैसे दल विपक्ष में रहने के बावजूद गठबंधन में शामिल नहीं हो रहे है। ऐसे में सवाल उठता है कि कुछ विपक्षी दल विपक्षी दलों के गठबंधन में शामिल क्यों नहीं हो रहे हैं? इसके दो कारण हैं। पहला कारण राजनीतिक है और दूसरा कारण वैचारिक है। 2014 में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली भाजपा ने कांग्रेस समेत अन्य दलों को राजनीतिक शिकस्त के साथ-साथ वैचारिक रूप से भी धराशायी कर दिया था। यह सच है कि भाजपा वैचारिक रूप से हिंदुत्व की पैरोकार है, और शिवसेना को छोड़ दें तो दूसरा कोई भी दल हिन्दुत्व की राजनीति नहीं करता। इसलिए 2014 और 2019 की बंपर जीत से भाजपा ने सेकुलर दलों के सामने वैचारिक धरातल पर कड़ी चुनौती पेश की। अमेरिका दौरे के दौरान राहुल गांधी ने कहा है कि मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी अगले चुनाव में बहुत अच्छा करेगी। इसका कारण वह कांग्रेस की धर्मनिरपेक्षता और कल्याणकारी राजनीति बताते हैं। कर्नाटक चुनाव में कांग्रेस के भविष्य की राजनीति का संकेत भी मिल रहा है। 2024 के आम चुनाव में मुसलमान, दलित और अति पिछड़े कांग्रेस की तरफ जा सकते हैं।

सांसद पांडेय ने लिखा पत्र, केंद्र करेगा नेशनल हाईवे-130ए की गुणवत्ता जांच

कबीरधाम। छत्तीसगढ़ से होकर निकल रहे नेशनल हाईवे-130ए की गुणवत्ता की जांच अब केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय करेगा। इसे लेकर मंत्रालय की ओर से मुख्य अभियंता को पत्र भेजा गया है। प्रदेश के पोंडी से मुंगेली के बीच हाईवे पर निर्माण कार्य को लेकर सवाल खड़े हुए हैं। राजनांदगांव से सांसद संतोष पांडेय ने इसे लेकर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी को दो मई को पत्र भी लिखा था। इसमें कहा था कि, गुणवत्ताहीन व मापदंड़ो के विपरीत सड़क निर्माण किया जा रहा है। इसके चलते हादसे हो रहे हैं। एक दिन पहले ही इसी मार्ग पर लखनऊ जा रही बस भी पलट गई थी। हादसे में 20 लोग घायल हुए थे।

सड़क पर मिट्टी का अधिक इस्तेमाल

सांसद संतोष पांडेय की ओर से केंद्रीय सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी को लिखे पत्र में कहा गया कि, पोंडी से मुंगेली के बीच मिट्टी का अधिक उपयोग किया जा रहा है। खराब सड़क के चलते कई दुर्घटनाएं भी हो रही हैं। ठेकेदार के द्वारा किए जा रहे इस प्रकार के निर्माण से केंद्रीय सड़क परिवहन प्राधिकरण की छवि धूमिल करने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने सड़क निर्माण कार्य की जांच कर गुणवत्तापूर्ण निर्माण के लिए निर्देशित करते हुए दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की थी। इसी के आधार पर सड़क एवं परिवहन मंत्रालय ने जांच के आदेश जारी किए हैं।

मुख्य अभियंता को जांच के निर्देश

सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्रालय के सहायक अभियंता ने हाईवे के गुणवत्ताहीन निर्माण कार्य का परीक्षण/निरीक्षण कर आगे की कार्रवाई के लिए अनुशंसा की है। साथ ही लोक निर्माण विभाग राष्ट्रीय राजमार्ग परिक्षेत्र रायपुर के मुख्य अभियंता को पत्र लिखा है। यह हाईवे बेहद ही महत्वपूर्ण है। यह मार्ग बिलासपुर से जोड़ता है। इस मार्ग में बड़ी संख्या में यात्री बस, दो पहिया, चार पहिया वाहन के अलावा बड़े वाहन भी चलते हैं। गुणवत्ताहीन सड़क निर्माण होने से राहगीरों को परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। बीते माह बारिश होने से सैकड़ों वाहन इस मार्ग में फंस गए थे।

बस का शीशा तोड़कर बचाया गया था यात्रियों को

दो दिन पहले मंगलवार देर शाम कबीरधाम से यात्रियों को लेकर लखनऊ जा रही,ष्ट बस ग्राम परसवारा के पास पोड़ी-पंडरिया नेशनल हाईवे पर अनियंत्रित होकर पलट गई थी। रफ्तार तेज होने के चलते बस फिसलते हुए खेत में जा गिरी। इसके बाद यात्रियों में चीख-पुकार मच गई। आसपास के लोगों और राहगीरों ने हादसा होते देखा तो बस के आगे का शीशा तोड़कर अंदर फंसे यात्रियों को बाहर निकाला था। इसके चलते बस में सवार महिलाओं और बच्चों सहित 20 यात्री घायल हो गए थे। हाईवे पर एक तरफ सड़क की हाइट काफी ज्यादा है और दूसरी तरफ तीन से चार फीट का गहराई है।

मंत्री भगत ने अंधेरी घाटी मार्ग पर चल कर किया सड़क का सर्वे

अम्बिकापुर। खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण, योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी तथा संस्कृति मंत्री अमरजीत भगत सीतापुर विधानसभा के दौरे पर रहे। इस दौरान उनके निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले रकेली (गांगझरिया) तक 2.5 किमी पैदल अंधेरी घाटी मार्गों को पार करते हुए पहुंचे। इस पहुंच मार्ग का पैदल सर्वे करने के बाद सड़क निर्माण हेतु जिला कलेक्टर से चर्चा कर जल्द कार्यवाही के आदेश दिए। साथ ही यहां आंगनबाडी भवन निर्माण हेतु भूमिपूजन किया। इस दौरान मैनपाट में वैवाहिक कार्यक्रमों, शोकाकुल परिजनों से भेंट किया। विभिन्न पूजन कार्यक्रम में शामिल हुए और जनचौपाल कार्यक्रम में आमजनों के साथ-साथ कार्यकर्ताओं और जनप्रतिनिधियों से मुलाकात की।

कल के कार्यक्रम के दौरान मंत्री अमरजीत भगत ने मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क निर्माण योजना के अंतर्गत सड़क के निर्माण हेतु कार्यवाही आगे बढ़ाने के निर्देश दिए। साथ ही पीएचई विभाग के अधिकारियों से बात कर 2-3 जगहों पर बोर करने के निर्देश दिए। साथ ही यहां आंगनबाडी केंद्र के सुचारू संचालन के लिए ज़रूरी कदम उठाने का निर्देश अधिकारियों को दिया। इस अवसर पर उन्होंने ग्रामीणों से चर्चा के दौरान कहा कि बिजली विभाग से सहमति बनी गई है, बिजली सुविधाओं को बेहतर कर गांव को रोशन किया जाएगा?। साथ ही गांव वालों की आवश्यकता के अनुरूप अतिरिक्त छोटी बड़ी समस्याओ को दूर किया जाएगा।

देर रात दौरे से वापस आते वक़्त दरिमा के निकट बाइक सवार बीच सड़क पर घायल पड़ा था जिसे देख मंत्री ने काफिला रोका और अपने काफिले की गाड़ी से ही शीघ्र उपचार हेतु अस्पताल भिजवाया। मैनपाट के सरभंजा में स्वर्गीय सीताराम जी की स्मृति में क्रिकेट प्रतियोगिता आयोजित हुई। इसके समापन कार्यक्रम में मंत्री श्री भगत बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। यह इस क्रिकेट प्रतियोगिता का शानदार दूसरा वर्ष है। इस अवसर पर स्व. सीताराम का स्मरण करते हुए मंत्री श्री अमरजीत भगत ने कहा, स्व. सीताराम का मुझसे और पूरे मैनपाट और सरभंजा से अटूट प्रेम और विश्वास रहा है।

फ़ाइनल मुक़ाबले में रोपाखार की टीम विजेता रही व सरभंजा क्रिकेट क्लब उपविजेता रही, विजेता को 22000 रुपये नगद व उपविजेता को 11000 रुपये नगद पुरुस्कार से मंत्री श्री भगत ने पुरुस्कृत किया। मंत्री श्री भगत ने स्वेच्छा अनुदान मद से मैनपाट के 25 हितग्राहियो को शिक्षा, स्वास्थ्य और स्वरोजगार हेतु सहायता राशि का चेक का वितरण किया। इस दौरान कार्यक्रम में प्रतिनिधि मौजूद रहे जिनमे लालचंद यादव, रामचन्दन पोर्ते (सरपंच), संजय गुप्ता, सुरेश गोयल, संदीप जायसवाल, द्वारिका दुबे, प्रमोद टोप्पो, सियाबर रजवाड़े, राजेश महंत, नगीना यादव सहित बड़ी संख्या में ग्राम वासी मौजूद रहे।

हनोदा के ग्रामीण प्राथमिक शाला को स्थानांतरित कराने अड़े, सरपंच और कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन

दुर्ग। दुर्ग ब्लाक के ग्राम हनोदा में बजरंग प्रागण भांठापारा के बगल में जर्जर हो चुके पुराने शासकीय प्राथमिक शाला का निर्माण किया जा रहा है।जिसके विरोध ग्राम वासियों द्वारा किया जा रहा।ग्रामवासियों का कहना है कि यह स्कूल सड़क से लगा हुआ है और सड़क चौड़ी कारण होने के कारण वाहनों की आवा जाहि बहुत बढ़ चुकी है जिसके कारण छोटे छोटे बच्चों को रोड पार करने व आने जाने में समस्या हो रही है जिसकी वजह से 3-4 बच्चों का एक्सीडेंट भी चुका है।जिसे देखते हुए ग्रामवासी ने पहले अक्ती के अवसर पर सरपंच को आवेदन दिया गया लेकिन सरपंच ने इसे सिरे से नकारते हुए स्कूल को स्थानांतरित करने से मना कर दिया जिसके बाद गांव वाले हतास हो गए और कुछ दिनों में ही स्कूल का काम चालू कर दिया गया।लेकिन स्कूल का काम चालू होते देख ग्रामवासियों ने ग्रामीण स्तरीय बैठक रखा जिसमे ग्राम के सभी प्रबुद्धजन उपस्थित थे।जिसमे पंचायत प्रतिनिधियों को भी बुलाया गया था लेकिन बैठक में सिर्फ उपसरपंच एवं कुछ पंच ही उपस्थित हुवे,जिसके बाद ग्रामवासियों द्वारा फैसला लिया गया कि जो भी करना पड़े हम करेंगे हमारे बच्चों को रोड की आवा जाहि व दुर्घटनाओं से बचाने के लिए ।जिसके बाद बैठक में

सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि सर्वप्रथम पुन: ग्राम पंचायत में आवेदन दिया जाए जिसके अगले ही दिन सरपंच को स्थानांतरित करने आवेदन दिया गया लेकिन सरपंच ने कार्य प्रारंभ होने के कारण इसपर रोक लगाने व स्थांतरण करने से मना कर दिया,कोई भी कार्यवाही नही होने के कारण ग्रामीण सीधा जिलाधीश महोदय के पास जनदर्शन में पहुँच गए। जिसपर जिलाधीश महोदय द्वारा मांग को उचित समझते हुए ज्ञापित आवेदन पर त्वरित कार्यवाही करते हुए प्राथमिक शाला को स्थानांतरित करने पर सहमति प्रदान दी।अंतत: कार्य पूरा होने से गांव वालो के चेहरे में मुश्कान आयी।लेकिन आज भी स्कूल प्रांगण में निर्माण कार्य प्रगति पर है जिसके बाद ग्रामीणों ने ठेकेदार को स्थल पर बुला कर,कलेक्टर महोदय के आदेश आते तक काम रोकने को कहा गया लेकिन ऊपर से कोई आदेश नहीं आने के करण ठेकेदार ने काम बंद करने से मना कर दिया।अब आज निर्माण कार्य रुकवाने ग्रामीण अभियांत्रिकी सेवा अधिकारी के पास आवेदन जमा किया गया।ग्रामवासियों का कहना है कि हमारी मांग को स्वीकार नहीं किया गया तो पूरे ग्रामवासी द्वारा उचित कदम उठाया जाएगा।इस अवसर पर अभयराम साहू, बसंत चंदेल, भोजराम साहू, गौकरण टंडन, राजकुमार साहू, राजनाथ योगी, मनहरण साहू, बुधराम साहू, दानु यादव, दशरथ सांडिल्य, रमेश यादव, प्रवीण चंद्रकार उपसरपंच, दयालु टंडन पंच, चतुर साहू पंच, संजय यादव पंच, किशन साहू, बुधारू चंद्रकार, कालू यादव, रेखराम साहू, मितुल चंद्रकार, शेखर साहू, प्रकाश पटेल, राकेश साहू, रविश साहू, भूपेंद्र कुम्भकार, दौलत यादव, अनूप यादव, परमानंद चंद्रकार, अनिल साहू, घनश्याम कुर्रे, सागर चेलक, नियुराज कुर्रे, बुधराम चंद्रकार, लोकेश साहू, हरि साहू, भानुप्रताप कोषरे, धनंजय पटेल उपस्थित थे।

बालोद में पहुंची 1500 ईवीएम फर्स्ट लेवल चेकिंग शुरू

बालोद। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारियों में तेजी आ गई है। आने वाले तीन महीनों में चुनाव के दिन और करीब आ जाएंगे। ऐसे में राजनीतिक दलों के साथ-साथ प्रशासन भी तैयारियों में जुट गया है। बालोद के ग्राम झलमला से लगे पाकुरभाट को स्ट्रांग रूम में तब्दील किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि करीब 1500 ईवीएम पहुंच चुकी है और फर्स्ट लेवल चेकिंग शुरू कर दी गई है। ये पूरे जून महीने तक चलेगी। पारदर्शिता के लिए राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को भी बुलाया गया है।

बालोद पहुंची इन ईवीएम की निगरानी खुद कलेक्टर कुलदीप शर्मा और एसपी डॉक्टर जितेंद्र यादव कर रहे हैं। कलेक्टर कुलदीप शर्मा ने बताया कि विधानसभा चुनाव को देखते हुए चुनाव के पूर्व तैयारी चल रही है। ताकि चुनाव के समय किसी भी प्रकार की परेशानी और मशीनों में खराबी न आए। स्ट्रांग रूम में लगभग 1500 ईवीएम रखी हुई है। सभी की जांच की जा रही है। खराब मशीनों को अलग किया जा रहा है जांच 27 जून तक चलेगी। बताया कि चुनाव से पहले राजनीतिक दलों के साथ बैठक की जा रही है।

सुरक्षा को देखते हुए लाइव वेब कास्टिंग

निर्वाचन आयोग की ओर से ईवीएम की सुरक्षा को लेकर तगड़ी व्यवस्था की गई है। स्ट्रांग रूम की खिड़कियों को ईंट से पैक किया गया है। निगरानी के लिए 24 घंटे पुलिसकर्मियों की ड्यूटी लगाई गई है। निर्देशों से उन्हें अवगत कराया जा रहा है। सुरक्षा को देखते हुए लाइव वेबकास्टिंग चल रही है, जिसका सीधा कनेक्शन सीईओ छत्तीसगढ़ के पास है। वहीं स्ट्रांग रूम में सीसीटीवी कैमरे इत्यादि भी इंस्टॉल किए जा रहे हैं। मशीनों के जांच के लिए हैदराबाद से इंजीनियर भी पहुंचे हुए हैं।

नौ शिकारी चढ़े वन विभाग के हत्थे, घर से मिले जानवरों के अंग

गरियाबंद। वन्य जीवों का शिकार कर उनके अंगों की तस्करी और विक्रय करने वाले 9 आरोपियों को उदंती सीतानदी टाइगर प्रोजेक्ट की टीम ने गिरफ्तार किया है।

सूत्रों ने बताया कि वन्य जीवों का शिकार कर उनके अंग, खाल, नाखून, सिंग आदि की तस्करी और विक्रय करने वाले शिकारियों के खिलाफ टीम लगातार नजर रखे हुए थे। पकड़े गए सभी शिकारी इंदागांव के रहने वाले हैं। वन विभाग द्वारा लगातार की जा रही कार्रवाई के डर से सभी भागकर ओडिशा चले गए थे। बीते दिनों वन विभाग ने इनके घर पर छापा मारकर शिकार करने के सामान सहित सांभर के 12 सिंग तथा दुर्लभ पेंगोलिन का मांस बरामद किया था, जिसके बाद आज सुबह अचानक फ्रार नौ आरोपियों के घर पर दबिश देकर वन विभाग ने उन्हें गिरफ्तार किया है। ज्ञात हो कि पिछले कुछ दिनों से उदंती सीतानदी टाइगर प्रोजेक्ट इलाके में वन विभाग अवैध शिकार के मामले को लेकर काफी सक्रिय हो गया है। बीते 1 माह के भीतर बाघ की खाल के टुकड़े तेंदुए की खाल के टुकड़े भालू का पंजा सहित कई वन्यजीवों की हड्डियां तथा अन्य सामान वन्यजीव तस्करों से बरामद किए जा चुके हैं। वन विभाग जहां तस्करों पर लगातार कार्रवाई कर रहा है तो वहीं इससे बड़ा सवाल यह भी उठ रहा है कि उदंती सीतानदी टाइगर रिजर्व इलाके तथा आसपास के उड़ीसा के जंगलों में बड़े पैमाने पर शिकार हो भी रहा है तभी कार्रवाईयों में कई वन्यजीवों के अंग मिल रहे हैं।

छत्तीसगढ़ प्रमुख समाचार

आज से 15 अगस्त तक मत्स्याखेट पूर्णतः प्रतिबंध

कांकेर। वर्षा ऋतु में मछलियों की वंश वृद्धि (प्रजनन) को दृष्टिगत रखते हुये उन्हें संरक्षण देने हेतु जिले में छत्तीसगढ़ नदीय मत्स्योद्योग अधिनियम-1972 की धारा-3 उपधारा-2 (दो) के तहत 16 जून से 15 अगस्त तक की अवधि को बंद ऋतु (क्लोज सीजन) के रूप में घोषित किया गया है। इस दौरान जिले के समस्त नदी-नालों तथा छोटी नदियों, सहायक नदियों में जिन पर सिंचाई के बड़े या छोटे तालाब, जलाशय में सभी प्रकार का मत्स्याखेट 16 जून से 15 अगस्त 2023 तक पूर्णतः प्रतिबंध रहेगा। इन नियमों का उल्लंघन करने पर छत्तीसगढ़ राज्य मत्स्य क्षेत्र संशोधित अधिनियम के नियम-3 (5) के अन्तर्गत अपराध सिद्ध होने पर एक वर्ष का कारावास अथवा 10 हजार रूपये का जुर्माना अथवा दोनों एक साथ होने का प्रावधान है। उक्त नियम छोटे तालाब या अन्य जल स्त्रोत जिनका संबंध किसी नदी नाले से नहीं है, उसमें लागू नहीं होगा।

बिना नंबर प्लेट से लेकर नो पार्किंग तक काटे चालान

जगदलपुर। जगदलपुर शहर में लगातार नियमों की अवहेलना करने के साथ नियमों को तोड़ने वाले वाहन चालकों के ऊपर यातायात पुलिस के द्वारा कार्रवाई की जा रही है। जिसका सबसे बड़ा कारण है कि पुलिस ने ढाई माह में 2500 लोगों के लगभग वाहनों पर कार्य किया गया है। मामले के बारे में जानकारी देते हुए यातायात प्रभारी शिव शंकर गेंदले ने बताया कि अप्रैल से लेकर जून के बीच में यातायात पुलिस द्वारा हाईवे से लेकर मैन रोड, चौपाटी और अन्य जगहों पर सही तरीके से वाहनों को रखने से लेकर नो पार्किंग, 3 सवारी, काली फिल्म, मॉडल साइलेसर, शराब पीकर वाहन चलाने समेत अन्य मामलों में ट्रैफिक पुलिस ने कार्रवाई की है। वहीं समय-समय पर यातायात पुलिस द्वारा जागरूकता अभियान भी चलाया जाता है। जिसमें नाबालिकों को वाहन न देने से लेकर तेज रफ्तार वाहन न चलाने से लेकर होने वाले सड़क हादसे से बचने आदि का प्रयोग बताया जाता है। इन सबके अलावा वाहन चलाने के दौरान हेलमेट पहनकर चलने की सलाह दी जाती है।

अवैध रूप से रखी चिरान लकड़ी के साथ दो गिरफ्तार

कोरबा। छत्तीसगढ़ के कोरबा में वन विभाग की टीम ने गुरुवार को अवैध लकड़ी की सूचना पर छापा मारा। टीम ने एक मकान की बाड़ी में संचालित आरा मशीन और एक अन्य मकान से 128 नग चिरान लकड़ी बरामद की है। वन विभाग की टीम ने इस मामले में दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। दोनों के खिलाफ वन अधिनियम के तहत कार्रवाई की जा रही है। मामला कटघोरा वन मंडल क्षेत्र का है। जानकारी के मुताबिक, कटघोरा वनमंडल की टीम ने पाली वन परिक्षेत्र के ग्राम खम्हरिया में सौखीलाल सतनामी को गिरफ्तार किया है। उसने अपने घर की बाड़ी में आरा मशीन लगा रखी थी। उसके साथ ही टीम ने प्रमोद नामक ग्रामीण के घर छापामार कर 128 नग अवैध चिरान लकड़ी जब्त की। वन विभाग को लंबे समय से अवैध कार्यों की शिकायत मिल रही थी।

एसईसीएल एटक के नए पदाधिकारियों को जिम्मेदारी

कोरबा। संगठन को मजबूत करते हुए ठेका कर्मी और भू-विस्थापित के बीच आपसी तालमेल बैठाकर काम करना होगा। एसईसीएल में एटक के प्रति कर्मियों का भरोसा बढ़ा है। संगठन के प्रति इस विश्वास पर खरा उतरने का प्रयास किया जा रहा है। एटक मजदूरों के हित की लड़ाई लड़ता रहा है। आगे भी मजदूरों के लिए संगठन संघर्ष करता रहेगा। उक्त कथन एसकेएमएस एटक द्वारा कुसमुण्डा क्षेत्र में आयोजित क्षेत्रीय सम्मेलन में एटक के केंद्रीय महामंत्री हरिद्वार सिंह ने कही। सम्मेलन में केंद्रीय अध्यक्ष अजय विश्वकर्मा, केंद्रीय उप महामंत्री रामायण कुलदीप, गेवरा क्षेत्र से एलपी अघरिया क्षेत्रीय अध्यक्ष, दीपक उपाध्याय क्षेत्रीय सचिव, दीपका क्षेत्र से संजीव शर्मा क्षेत्रीय अध्यक्ष, सीके सिन्हा क्षेत्रीय सचिव भटगांव, मनोज पाण्डेय क्षेत्रीय सचिव, अखलाक खान क्षेत्रीय अध्यक्ष व रायगढ़ क्षेत्र के क्षेत्रीय अध्यक्ष जनक पाटिल मौजूद रहे। सम्मेलन में सर्वसम्मति से वीरेन्द्र कुमार टंडन क्षेत्रीय अध्यक्ष, अजीत कुमार सिंह क्षेत्रीय सचिव के पद पर चुने गए।

तीन ट्रकों की आपस में भिड़ंत फंसे चालक की हालत गंभीर

जशपुरनगर। गुरुवार की सुबह पत्थलगांव थाना क्षेत्र के रायगढ़ रोड के टावर लाइन के पास तीन ट्रकों में जबर्दस्त भिड़ंत हो गई जिसमें एक ट्रक का चालक क्षतिग्रस्त ट्रक के केबिन में फंस गया जिसे बड़ी मुश्किल से बाहर निकाला गया। गंभीर अवस्था में उसे पत्थलगांव के सिविल अस्पताल में भर्ती किया गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार ट्रक क्रमांक यूपी 70 एफटी 9613 रायगढ़ से लोहा का एंगल लोड करके उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के लिए रवाना हुआ था। पत्थलगांव के पास अचानक यह ट्रक अनियंत्रित होकर सामने से आ रहे ट्रक क्रमांक सीजी 15 डीएफ को जबरदस्त ठोकर मारा। यह ट्रक अंबिकापुर के सोनभद्र से कोयला लेकर रायगढ़ की ओर जा रही थी। ठोकर से इस ट्रक का संतुलन बिगड गया और यह आगे चल रही एक अन्य ट्रक सीजी 29 एसी 1550 से जाकर टकरा गया। इस दुर्घटना में तीनों ट्रक बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए। हादसे में एंगल लोड ट्रक का परिचालक केबिन में फंस गया। घटना की सूचना पर मौके पर पत्थलगाव पुलिस की टीम पहुंची।

कोरबा महापौर ने किया वार्ड 7 का भ्रमण, लोगों की जानी समस्याएं

कोरबा। महापौर राजकिशोर प्रसाद ने वार्ड क्र. 07 अंतर्गत कुंजनगर, आश्रय होटल के पीछे, मोतीसागरपारा, बजरंग बली मंदिर के समीप आदि बस्तियों का भ्रमण करते हुए स्वच्छता संबधित सफाई व्यवस्था एवं नालियों की साफ-सफाई का जायजा लिया। भ्रमण के दौरान महापौर श्री प्रसाद ने लोगों की समस्याएं सुनी तथा वार्डवासियों की पानी की समस्याओं से अवगत हुये। स्वच्छता दीदियों से स्वच्छता के संबंध में जानकारी हासिल करते हुए जाना कि कचरों का उठाव नियमित रूप से हो रहा है या नहीं, जानने के अलावा उनको निर्देशित करते हुए महापौर ने कहा कि किसी भी घर में कचरा छूटना नहीं चाहिए।

भ्रमण के दरम्यान वार्ड क्र. 07 अंतर्गत कुंजनगर, आश्रय होटल के पीछे, मोतीसागरपारा, बजरंग बली मंदिर के समीप सड़क निर्माण कार्य के दौरान पानी की पाईप लाईन क्षतिग्रस्त हो गई थी जिसे

महापौर ने तत्काल क्षतिग्रस्त लाईन को दुरूस्त करने के निर्देश अधिकारियों को दिये। लोगों की समस्याएँ सुनी तथा वार्डवासियों की छोटी-छोटी मांगे जैसे नालियों का कहीं टूट-फूट होना, नालियों में ढक्कन लगवाने की मांग तथा चबूतरा निर्माण की मांग वार्डवासियों द्वारा रखे जाने पर महापौर के साथ चल रहे अधिकारियों को उनकी मांगों का त्वरित निदान करने हेतु आदेशित किया। नगर पालिक निगम कोरबा द्वारा वार्डो में नाले-नालियों की सफाई, निकले अपशिष्ट का उसी कार्यदिवस में उठाव एवं उनका परिवहन, सड़कों, सार्वजनिक स्थलों पर झाड़ू लगाना, डोर-टू-डोर अपशिष्ट एकत्रीकरण, नालियों एवं सार्वजनिक स्थलों में कीटनाशक एवं लार्वा मच्छरनाशक दवाओं का छिड़काव आदि का कार्य करते हुए पेयजल, सड़क, रोशनी आदि सेवाएं निर्वाध रूप से जारी रखने हेतु अलग-अलग विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिये। हालाकि स्वच्छता अभियान में नगर पालिक निगम कोरबा के अधिकारी कर्मचारीगण युद्धस्तर पर बारिश के पूर्व कोरबा को स्वच्छ बनाने के अभियान में भिड़े हुए हैं, उनके साथ महापौर की उपस्थिति कार्यरत अधिकारियों कर्मचारियों में ऊर्जा का संचार भरने का कार्य की। महापौर श्री प्रसाद ने लोगों से इधर-उधर गली-मोहल्लों में कचरे को कहीं भी न फेंकने की समझाईश दी तथा अपने वार्ड एवं शहर को स्वच्छ रखने में अपनी भी अहम भूमिका निभाने की अपील की।

निरीक्षण के दौरान पार्षद संतोष लांझेकर, एस.डी.सिंह, गौरीशंकर महंत, लक्ष्मी सागर, चिंतामणी केंवट, परदेशी चौहान, गजराज यादव, ज्योति महंत आदि के साथ निगम के अधिकारी कर्मचारीगण उपस्थित थे।

बादल मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की दूरगामी सोच का परिणाम : रेखचंद जैन

■ समर कैंप के समापन कार्यक्रम में पहुंचे संसदीय सचिव

जगदलपुर। बादल (बस्तर एकेडमी ऑफ़ डांस आर्ट एंड लिटरेचर) की स्थापना छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की दूरगामी सोच का परिणाम है। जनजातीय बाहुल्य बस्तर की पहचान समूचे विश्व में है। विभिन्न जातियों में प्रचलित परंपराओं, रीति-रिवाजों तथा लोक विश्वास के संरक्षण की पहल सीएम के नेतृत्व व मार्गदर्शन में किया जा रहा है। समर कैंप का आयोजन इसी की कड़ी है। अपने स्कूली जीवन को याद कर बताया कि उनके समय गर्मी की छुट्टियों में बच्चे अपने नाना- मामा के यहां चले जाते थे क्योंकि ऐसा कोई भी आयोजन नहीं होता था लेकिन इस साल समर कैंप के माध्यम से कला, संस्कृति व बोली- भाषा का प्रशिक्षण प्रदान किया गया। उन्होने विश्वास जताया कि यह शुरुआत आगामी वर्षों में भी जारी रहेगी। श्री जैन ने समाज प्रमुखों के योगदान की भी सराहना की। कार्यक्रम को पार्षद सूर्या पाणि, हल्बा समाज के जितेन्द्र शार्दुल तथा अन्य लोगों ने भी संबोधित किया। संस्था प्रभारी अधिकारी पूर्णिमा सरोज ने प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। समापन अवसर पर गौरनाथ नाग, वरिष्ठ पत्रकार संतोष सिंह, सहायक आयुक्त संजय चंदेल, समाज प्रमुख लखेश्वर खुदराम, सामूराम मौर्य, हरिश्चंद्र नाग, सदाराम समरथ, त्रिलोकी प्रभुलिया, पिताम्बर अड़बड़िया, विद्याधर जीराम, पूनम गुप्ता, जयंती बघेल, दीप्ति ओग्रे, योगेश साहनी, नीलूराम कोर्राम, नुपुर दास, विशाल ठाकुर, विनीता पांडे, स्मृति पाढ़ी, सचिन लेवी पन्ना, दीपेश ध्रुव, दीपक कश्यप, प्रेरणा नाम, नेत्रकांत पानीग्राही, लीबरु सोढ़ी समेत प्रशिक्षणार्थी, उनके अभिभावक व अन्य बड़ी संख्या में मौजूद थे। कार्यक्रम संचालन भरत गंगादित्य व हितप्रिता ठाकुर ने किया। समापन समारोह में विविध विधाओं के प्रशिक्षणार्थियों ने अनेक मनमोहक प्रस्तुति दी।

राष्ट्रीय/अंतरराष्ट्रीय
प्रमुख समाचार

मोदी ने विश्वस्तरीय बुनियादी अवसंरचना का निर्माण किया

नयी दिल्ली। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बृहस्पतिवार को कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) सरकार के नौ साल के कार्यकाल में विश्व स्तरीय बुनियादी अवसंरचना का निर्माण कर विकसित भारत की नींव रखी है। शाह ने यह भी कहा कि सुस्त परियोजनाओं को पूरा करने से लेकर नयी परियोजनाओं को अभूतपूर्व तेजी के साथ लागू करने तक भारत 'गति और प्रगति' के नौ वर्षों में वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला के नेता के रूप में उभरा है। उन्होंने ट्वीट किया, ''प्रधानमंत्री ने निर्बाध संपर्क सुनिश्चित करने में असाधारण प्रगति के साथ एक विकसित भारत की नींव रखी।'' प्रधानमंत्री ने नौ वर्षों में विकास को गति देने के लिए बुनियादी ढांचे के निर्माण में तेजी लाकर भारत को आगे बढ़ाया है। उन्होंने कहा, ''चाहे वह डिजिटल संपर्क हो, राजमार्ग व हवाई अड्डे का निर्माण हो या रेलवे को दूरदराज के इलाकों में पहुंचाना हो, विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचा अब भारतीय कहानी का मूल है।

द्रमुक नेता सेंथिल ने ईडी पर लगाया बुरे व्यवहार का आरोप

चेन्नई। तमिलनाडु राज्य मानवाधिकार आयोग के सदस्य वी कन्नदासन ने गुरुवार को द्रमुक सरकार के मंत्री और ईडी द्वारा गिरफ्तार सेंथिल बालाजी से अस्पताल में मुलाकात की। सेंथिल का आरोप है कि हिरासत में ईडी के अधिकारी उनके साथ बुरा व्यवहार कर रहे हैं। वहीं राज्य मानवाधिकार आयोग के सदस्य के सेंथिल से मुलाकात पर विपक्षी पार्टी अन्नाद्रमुक ने आपत्ति जताई है। बता दें कि ईडी ने सेंथिल बालाजी को नौकरी के बदले नकदी घोटाले में मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में गिरफ्तार किया था। ईडी की छापेमारी के दौरान सेंथिल बालाजी की तबीयत बिगड़ गई थी, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। फिलहाल सेंथिल अस्पताल में भर्ती हैं। गुरुवार को राज्य मानवाधिकार आयोग के सदस्य वी कन्नदासन ने सेंथिल से मुलाकात की। इस मुलाकात में सेंथिल ने आरोप लगाया कि ईडी की हिरासत में उन्हें घसीटा गया, जिससे उनके सिर में चोट आई है।

कांग्रेस की 'रेवड़ी राजनीति' ने कर्नाटक को किया लहुलुहान

नयी दिल्ली। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने बृहस्पतिवार को दावा किया कि कर्नाटक के वित्त विभाग ने वेतन और ईंधन पर हुए खर्च के भुगतान के लिए अतिरिक्त अनुदान प्रदान करने में असमर्थता व्यक्त की है। पार्टी ने राज्य की कांग्रेस सरकार पर यह कहते हुए तंज कसा कि क्या प्रदेश सरकार अब अपनी जेब से मुफ्त बस यात्रा का खर्च उठाएगी ? राज्य के वित्त विभाग के कथित पत्र की एक प्रति ट्विटर पर साझा करते हुए भाजपा के सूचना और प्रौद्योगिकी विभाग के प्रमुख अमित मालवीय ने कहा, ''रेवड़ी राजनीति ने कर्नाटक को लहूलुहान किया।' उन्होंने कहा, 'कर्नाटक सरकार के वित्त विभाग ने केएसआरटीसी (कर्नाटक राज्य सड़क परिवहन निगम) और बीएमटीसी (बेंगलुरु महानगर परिवहन निगम) सहित आरटीसी (सड़क परिवहन निगम) को सूचित किया है कि वह वेतन और ईंधन व्यय के भुगतान के लिए अतिरिक्त अनुदान प्रदान नहीं कर सकता।'

केंद्र का अध्यादेश सत्ता हथियाने का 'निर्लज्ज' हथकंडा: केजरीवाल

नयी दिल्ली। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सेवाओं पर नियंत्रण से संबंधित केंद्र सरकार के अध्यादेश को सत्ता हथियाने का हथकंडा करार देते हुए कहा कि यह उच्चतम न्यायालय में टिक नहीं पाएगा और एकजुट विपक्ष इसे राज्यसभा में गिरा सकता है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (भाकपा) के महासचिव डी. राजा के साथ बैठक के बाद यहां संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए केजरीवाल ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार ने व्यावहारिक रूप से पूरी दिल्ली सरकार को अपने कब्जे में ले लिया है। केजरीवाल यह सुनिश्चित करने के लिए विपक्षी नेताओं से मिलते रहे हैं कि संबंधित विधेयक राज्यसभा में पारित न हो। मुख्यमंत्री ने अध्यादेश को सत्ता हथियाने का 'निर्लज्ज' हथकंडा करार दिया और कहा कि इससे दिल्ली में तबाही मच जाएगी। उन्होंने दावा किया कि अध्यादेश ने उच्चतम न्यायालय की संविधान पीठ के फैसले को पलट दिया है।

अठावले ने महाराष्ट्र कैबिनेट विस्तार में मांगा मंत्री पद

मुंबई। महाराष्ट्र में शिवसेना-भाजपा गठबंधन जल्द ही कैबिनेट विस्तार करने पर विचार कर रही हैं। इसके लिए मंथन चल ही रहा है कि गठबंधन की सहयोगी पार्टी रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया ने भी अपने लिए एक मंत्री पद की मांग कर दी है। बुधवार रात में मुंबई के बाहरी इलाके में आरपीआई कार्यकर्ताओं की एक बैठक को संबोधित करते हुए पार्टी अध्यक्ष रामदास अठावले ने बताया कि उन्होंने महाराष्ट्र में अगले मंत्रीमंडल विस्तार में अपनी पार्टी के लिए एक मंत्री पद की मांग की है। रामदास अठावले ने कहा कि उन्होंने उचित फोरम पर अपनी यह मांग रख दी है। उन्होंने ये भी कहा कि वह कोशिश करेंगे कि महाराष्ट्र में आरपीआई (अठावले) को दो से तीन लोकसभा सीटें और 10-15 विधानसभा सीटों पर टिकट दिए जाएं। अठावले ने ये भी कहा कि उनकी पार्टी शिवसेना-भाजपा गठबंधन के साथ मिलकर निकाय चुनाव और जिला परिषद के चुनाव भी लड़ेगी।

भाजपा को नकारात्मक फीडबैक को सकारात्मक में बदलने की चुनौती

भोपाल। एक तरफ जहां राष्ट्रीय नेताओं के राज्य में दौरे हो रहे हैं तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह और पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा का दौरा प्रस्तावित है। राज्य में वर्ष 2018 में हुए विधानसभा चुनाव में भाजपा को डेढ़ दशक तक सत्ता में रहने के बाद बाहर होना पड़ा था और कांग्रेस के हाथ सत्ता आ गई थी। कांग्रेस में छिड़े भीतरी संघर्ष के चलते ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ 22 विधायकों ने कांग्रेस का साथ छोड़ा और कमलनाथ के नेतृत्व वाली सरकार गिर गई थी, जिससे भाजपा फिर सत्ता में आ गई।

राज्य में इसी साल विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं और वर्ष 2018 के नतीजों से भाजपा सबक ले चुकी है, लिहाजा उसने आगामी विधानसभा चुनाव से पहले जमीनी सर्वे कराए हैं। सर्वे रिपोर्ट ने भाजपा की चिंता बढ़ा दी है। लिहाजा, पार्टी सर्वे को गंभीरता से लेने के साथ जमीनी हालात में सुधार लाने की कोशिशों में जुट गई है।

राज्य में भाजपा का विशेष जनसंपर्क अभियान चल रहा है, इसमें देश के अलग-अलग हिस्सों की नेता दौरे पर हैं और नरेंद्र मोदी के नौ साल का ब्यौरा दे दे रहे हैं। कुल मिलाकर भाजपा केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं की चर्चा कर बदलते देश की तस्वीर भी पेश कर रहे हैं।

भाजपा के राष्ट्रीय नेताओं का जहां एक तरफ राज्य में दौरा चल रहा है, वही आगामी दिनों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह और पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा का मध्य प्रदेश का दौरा प्रस्तावित है। पार्टी प्रधानमंत्री सहित अन्य नेताओं के दौरे के जरिए राज्य का सियासी माहौल बदलना चाहती है, इसीलिए राष्ट्रीय नेतृत्व की मध्य प्रदेश पर हाथ नजर भी है।

राज्य के वर्ष 2018 के विधानसभा चुनाव पर नजर दौड़ाई जाए तो 230 विधानसभा सीटों में से भाजपा को 109 सीटें ही मिली थी और कांग्रेस 114 सीटें लेकर बहुमत के करीब पहुंच गई थी। सपा, बसपा व निर्दलीय विधायकों का समर्थन मिलने के चलते कांग्रेस की कमलनाथ के नेतृत्व में सरकार बनी। लगभग 15 मई यह सरकार चली और ज्योतिरादित्य सिंधिया की नाराजगी के चलते 22 विधायकों ने पार्टी छोड़ दी, जिससे कमलनाथ की सरकार अल्पमत में आ गई और आगे चलकर भाजपा ने शिवराज के नेतृत्व में फिर सरकार बनाई। उपचुनाव में भाजपा को बड़ी सफलता मिली और पूर्ण बहुमत की सरकार बन गई।

नीतीश कुमार ने लोकसभा चुनाव पहले होने का लगाई आशंका

पटना। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने लोकसभा चुनाव इसी साल के अंत में कराए जाने की आशंका जताई है। इसके बाद से ही राजनीतिक माहौल गरम हो गया है। भाजपा नेता जहां नीतीश कुमार के इस बयान पर कोई टिप्पणी करने से बच रहे हैं, वहीं विपक्षी दलों का मानना है कि सरकार की लोकप्रियता में लगातार कमी आ रही है और वह हड़बड़ी में समय से पहले चुनाव करा सकती है।

केंद्र सरकार लगातार अपनी योजनाओं का प्रचार-प्रसार कर रही है। माना जा रहा है कि वह जल्द से जल्द जनता के पास सही संदेश बनाकर एक माहौल बनाकर चुनाव में उतरने की कोशिश कर सकती है। पार्टी के केंद्रीय इकाई के नेता जिस तरह लगातार बैठकें कर रहे हैं, उससे भी पार्टी की बड़े स्तर की तैयारी का अनुमान लगाया जा रहा है। ऐसे में यह आशंका जताई जा रही है कि सरकार समय से पहले चुनाव करा सकती है।

नीतीश कुमार ने अपने अधिकारियों के साथ एक मीटिंग के दौरान बुधवार को टिप्पणी करते हुए कहा कि वे योजनाओं को जल्द पूरा करें और सभी योजनाओं पर राज्य सरकार के द्वारा कराए जाने की पूरी जानकारी लिखें, जिससे जनता में इसका सही संदेश दिया जा सके। इसी क्रम में उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव समय से पहले भी कराए जा सकते हैं। हालांकि, इन आशंकाओं के बीच राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि यह राजनीतिक शिगूफा है और सरकार अभी इस तरह की कोई तैयारी नहीं कर रही है। विशेषकर यह देखते हुए कि जब पीएम नरेंद्र मोदी की सरकार कम समय में भी कई बार पूरा नैरेटिव बदलने की हैसियत रखती है, वह समय से पहले चुनाव कराने की गलती नहीं करेगी।

राजनीतिक विश्लेषक ने कहा कि अब तक के कई सर्वे यह बता रहे हैं कि सरकार लगातार लोकप्रिय बनी हुई है। आर्थिक मोर्चे पर सरकार ने वैश्विक स्तर पर अपनी क्षमता साबित कर दी है। कई सर्वे भी इस बात को प्रमाणित करते हैं कि पीएम नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता में कोई गिरावट नहीं हुई है, उलटे वह लगातार लोकप्रिय हो रहे हैं। ऐसे में सरकार समय से पहले चुनाव कराने की कोई गलती नहीं करेगी।

क्या नीतीश कुमार प्रधानमंत्री से बात की है : भाजपा

बिहार भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने गुरुवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर उनके उस बयान को लेकर निशाना साधा, जिसमें उन्होंने कहा था कि वह लोकसभा चुनाव समय से पहले होने का अनुमान लगा रहे हैं। चौधरी ने नीतीश से पूछा कि क्या उन्होंने इस बारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात की, जिससे उन्हें इतना यकीन हो गया। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बुधवार को कहा था कि लोकसभा चुनाव समय से पहले होने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। चौधरी ने नीतीश कुमार से पूछा केवल पीएम ही ऐसा फैसला ले सकते हैं, क्योंकि लोकसभा को भंग करने के लिए कैबिनेट के फैसले की जरूरत होगी। क्या उन्होंने इस पर पीएम से कोई बात की, या यह राजद का बढ़ता दबाव है जो उन्हें अटकलें लगाने पर मजबूर कर रहा? जनता दल-यूनाइटेड (जद-यू) ने चौधरी को यह कहते हुए तुरंत प्रतिक्रिया दी, इस साल के अंत में कुछ और राज्यों में चुनाव होने हैं और उन सभी में भाजपा की संभावनाएं धूमिल दिख रही हैं। 2024 से पहले और अधिक झटकों से बचने के लिए घबराई हुई भाजपा समय पूर्व चुनाव के बारे में सोच सकती है। इससे इंकार नहीं किया जा सकता है।

विपक्ष कर रहा है राज्य की छवि को धूमिल करने की कोशिश: ममता

कोलकाता । पंचायत चुनाव के नामांकन को लेकर राज्य में चल रहे खून खराबे को लेकर सीएम ममता ने मुंह खोला व विपक्ष पर जमकर बरसीं। उन्होंने कहा कि विपक्ष पंचायत चुनाव के नामांकन को उग्र कर रहा है, जिस वजह से हिंसा की घटनाएं बढ़ रही हैं। टीएमसी प्रमुख और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने महेशतल्ला में पार्टी कार्यालय के बाहर कहा कि जिन कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन बेहतर नहीं था, पार्टी ने इस बार उन्हें टिकट नहीं दिया। विपक्षी नेता नामांकन दाखिल करते समय हिंसा कर रहे हैं। वह राज्य की छवि को धूमिल करने की कोशिश कर रहे हैं। गुरुवार को चोपड़ा में हुई हिंसा को सीपीआई (एम) ने अंजाम दिया। जबकि, भांगोर में आईएसएफ हमारी पार्टी के कार्यकर्ताओं पर हमला कर रही है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भाजपा की केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि उन्होंने राज्य के बकाये फंड को रोक दिया है। केंद्रीय एजेंसियों का इस्तेमाल करके भाजपा टीएमसी नेताओं को डराने की कोशिश कर रही है। मंगलवार को उत्तर 24 परगना में इंडियन सेक्युलर फ्रंट और तृणमूल कांग्रेस के समर्थकों के बीच झड़प हुई थी। सेक्युलर फ्रंट ने सत्तारूढ़ पार्टी पर आरोप लगाया कि वह उन्हें नामांकन भरने से रोक रहे हैं। झड़प को शांत करने के लिए भारी संख्या में पुलिस बल मौके पर पहुंची थी। इस दौरान कई बम भी फेंके गए थे। वाहनों के साथ तोड़फोड़ भी की गई थी। झड़प में दोनों पार्टियों के कार्यकर्ता घायल हो गए थे। आईएसएफ नेता और भांगोर विधायक नौशाद सिद्दीकी ने टीएमसी पर आरोप लगाते हुए कहा था कि टीएमसी के गुंडे रात से ही हमारे उम्मीदवारों को नामांकन भरने से रोक रहे हैं। टीएमसी के प्रवक्ता कुणाल घोष ने इन आरोपों को नकारते हुए कहा कि आईएसएफ इलाके में हिंसा फैला रही थी। बता दे कि पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनाव के दौरान हिंसा का इतिहास रहा है। 2013 और 2018 के पंचायत चुनाव भी अपवाद नहीं थे। 2013 में जहां पंचायत चुनाव में हिंसा के चलते 39 लोगों की मौत हुई थी, वहीं 2018 में 21 लोग मारे गए थे। पिछले पंचायत चुनाव में 34 प्रतिशत सीटों पर टीएमसी निर्विरोध जीती थी, साथ ही 90 प्रतिशत सीटों पर टीएमसी समर्थित उम्मीदवारों ने ही जीत दर्ज की थी।

खेल
प्रमुख समाचार

एशिया कप 31 अगस्त से शुरू, 6 टीम और 13 मुकाबले

नई दिल्ली। एशियाई क्रिकेट परिषद (एसीसी) ने पुष्टि की कि एशिया कप 2023 टूर्नामेंट 31 अगस्त से 17 सितंबर के बीच खेला जाएगा। टूर्नामेंट पाकिस्तान में चार मैचों के साथ शुरू होगा। एसीसी हाइब्रिड मॉडल की स्वीकृति दी है। इस साल टूर्नामेंट एकदिवसीय प्रारूप में खेला जाएगा। अंतिम नौ मैच श्रीलंका में खेला जाएगा। फाइनल मुकाबला भी श्रीलंका में खेला जाएगा। एशिया कप 2023 भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, अफगानिस्तान और नेपाल की टीमें हैं। 2022 में संयुक्त अरब अमीरात में आयोजित फाइनल में पाकिस्तान को हराने के बाद श्रीलंका डिफेंडिंग एशिया कप चैंपियन है।

भारत को लीग चरण में पाकिस्तान और नेपाल के साथ रखा गया है, जबकि श्रीलंका, बांग्लादेश और अफगानिस्तान दूसरे समूह में हैं। दोनों समूहों की दो टीमें सुपर फोर राउंड-रॉबिन चरण में प्रवेश करेंगी। इसके बाद राउंड की दोनों टीमें फाइनल में पहुंचेंगी। इस एक दिवसीय क्रिकेट टूर्नामेंट को लेकर गतिरोध पिछले सप्ताह समाप्त हुआ, जब जय शाह की अगुवाई वाले एसीसी ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के हाइब्रिड मॉडल को मंजूरी दी। बीसीसीआई ने साफ तौर पर कहा था कि दोनों देशों के बीच जारी राजनीतिक तनाव कारण वह अपनी टीम पाकिस्तान नहीं भेजेगा। एसीसी ने एक बयान में कहा ,'हमें यह घोषणा करते हुए खुशी हो रही है कि एशिया कप 2023 31 अगस्त से 17 सितंबर तक खेला जायेगा, जिसमें भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, अफगानिस्तान और नेपाल की टीमें भाग लेंगी।' इसमें कहा गया ,'टूर्नामेंट हाइब्रिड मॉडल पर खेला जायेगा जिसमें चार मैच पाकिस्तान में और बाकी नौ श्रीलंका में खेले जायेंगे।' इस सत्र में दो समूहों में टीमों को बांटा जायेगा और हर समूह से शीर्ष दो टीमें सुपर चार चरण में पहुंचेंगी।

आर्थिक/वाणिज्य/विज्ञान/
प्रमुख समाचार

शेयर बाजार 311 अंक गिरकर 63 हजार के नीचे आया

नईदिल्ली। अमेरिकी फेडरल रिजर्व के आक्रामक रुख कायम रखने के संकेतों के बीच स्थानीय शेयर बाजार में निवेशकों की बैंकिंग, सूचना प्रौद्योगिकी और वित्तीय शेयरों में मुनाफावसूली से गुरुवार को प्रमुख सूचकांकों में तीन कारोबारी सत्रों के बाद गिरावट आई। कारोबारियों ने कहा कि यूरोपीय बाजारों में कमजोर शुरुआत और रुपये में नुकसान ने भी निवेशकों की जोखिम उठाने की धारणा पर असर डाला। बीएसई का 30 शेयरों वाला सूचकांक सेंसेक्स 310.88 अंक यानी 0.49 प्रतिशत गिरकर 62,917.63 पर बंद हुआ। कारोबार के दौरान एक समय यह 357.43 अंक तक गिर गया था। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 67.80 अंक यानी 0.36 प्रतिशत की गिरावट के साथ 18,688.10 पर बंद हुआ। इसके पहले तीन कारोबारी सत्रों में बाजार में बढ़त रही थी। सेंसेक्स में शामिल कंपनियों में विप्रो को सर्वाधिक 2% का नुकसान उठाना पड़ा।

डायरेक्ट म्यूचुअल फंड स्कीम के लिए सेबी ने नियम जारी किए

नईदिल्ली। मार्केट रेगुलेटर सेबी ने डिजिटल प्लेटफॉर्म जैसे जेरोधा और पेटीएम, जो कि निवेशकों को म्यूचुअल फंड के डायरेक्ट प्लान खरीदने के लिए अनुमति देते हैं, उनके लिए नियम तैयार किए गए हैं। बता दे कि सेबी ने फाइनल गाइडलाइन्स के साथ ही Execution Only Platforms (EOP) को लेकर डिटेल्ड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क तैयार करने के लिए पिछले साल के कंसल्टेशन पेपर सेटिंग को फॉलो किया है। ईओपी एक डिजिटल या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जो म्यूचुअल फंड की योजनाओं की डायरेक्ट प्लान में सब्सक्रिप्शन, रिडेम्पशन और स्विच लेनदेन जैसे लेनदेन की सुविधा देता है। सेबी के 13 जून के नोटिस के अनुसार, किसी भी इकाई को सेबी या एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया (एएमएफआई) से पंजीकरण प्राप्त किए बिना ईओपी के रूप में काम करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

टाटा स्टील का कम कार्बन एमिशन की टेक्नोलॉजी पर जोर

नईदिल्ली। टाटा स्टील ने कम कॉर्बन उत्सर्जन की इस्पात विनिर्माण प्रक्रिया के विकास के लिए जर्मनी के एसएमएस समूह के साथ भागीदारी की है। टाटा स्टील ने गुरुवार को बयान में कहा कि इस समझौता ज्ञापन (एमओयू) के तहत दोनों कंपनियां आगे तकनीकी चर्चा करेंगी और एसएमएस समूह द्वारा विकसित ईजीमेल्ट (इलेक्ट्रिक-एसिस्टेड सिनगैस स्मेल्टर) प्रौद्योगिकी का संयुक्त रूप से औद्योगिक प्रदर्शन करेंगी। बयान में कहा गया है कि यह प्रदर्शन टाटा स्टील के जमशेदपुर संयंत्र के ई ब्लास्ट फर्नेस में किया जाएगा। इसका उद्देश्य कॉर्बन उत्सर्जन में 50 प्रतिशत से अधिक की कमी लाना है। ईजीमेल्ट तकनीक एक लोहा बनाने वाला समाधान है जिसे मौजूदा इस्पात संयंत्रों को कॉर्बन-मुक्त करने के लिए लागू किया जा सकता है। टाटा स्टील के सीईओ और प्रबंध निदेशक टी वी नरेंद्रन ने कहा, ''हम सक्रिय रूप से हरित इस्पात उत्पादन की ओर बदलाव के लिए समाधान तलाश रहे हैं।

सिंपल एनर्जी की कम दाम के ई-स्कूटर उतारने की योजना

नईदिल्ली। इलेक्ट्रिक वाहन स्टार्टअप कंपनी सिंपल एनर्जी अगली तिमाही में दो नए ई-स्कूटर पेश करने की योजना बना रही है। कंपनी के संस्थापक सुहास राजकुमार ने यह जानकारी देते हुए कहा कि इन ई-स्कूटर का दाम उपभोक्ताओं के लिए 'आकर्षक' होगा। राजकुमार ने कहा कि कम कीमत के ई-स्कूटर के साथ कंपनी अपनी प्रस्तावित 10 करोड़ डॉलर का कोष जुटाने की योजना के तहत न केवल मौजूदा निवेशकों को कायम रख पाएगी, बल्कि वह संस्थागत निवेशकों को भी जोड़ पाएगी। कंपनी ने पिछले महीने अपना पहला प्रीमियम ई-स्कूटर सिंपल वन पेश किया था, जिसकी कीमत 1.45 लाख रुपये है। सात जून से कंपनी ने बेंगलुरु में चरणबद्ध तरीके से इस स्कूटर की आपूर्ति शुरू कर दी है।

आपस में जुड़ी दुनिया और मौद्रिक नीति की चुनौती

अजय शाह

ऐसा माना जा रहा था कि अमेरिकी केंद्रीय बैंक फेडरल रिजर्व, अमेरिकी खुदरा मूल्य सूचकांक को दो फीसदी के स्तर पर लाने का अपना लक्ष्य हासिल करने की ओर बढ़ रहा है। यह काम हाल के सप्ताहों में उस समय मुश्किल हो गया जब अमेरिकी अर्थव्यवस्था में मजबूती नजर आई और यूक्रेन से निरंतर निर्यात को लेकर चिंताएं उत्पन्न हुईं।

ऐसा प्रतीत होता है कि अमेरिका अब दरों में 50 और आधार अंकों की वृद्धि की ओर बढ़ रहा है। भारत की बात करें अमेरिकी फेड द्वारा और रिजर्व बैंक द्वारा कोविड के बाद के दौर में विस्तार पर काफी हद तक लगाम लगाए रखी गई है। रिजर्व बैंक की दरों में इजाफा न करने की नीति भी सही है।

सन 2021 में अमेरिकी फेड ने अमेरिका में मुद्रास्फीति की समस्या से निपटना शुरू किया और मार्च 2022 के बाद से दरों में 10 बार इजाफा किया। वहां अल्पावधि की दर अब 5 से 5.25 फीसदी के बीच है। उधर रूस ने फरवरी 2022 में यूक्रेन पर हमला कर दिया। इन दोनों घटनाओं ने विश्व अर्थव्यवस्था पर नया दबाव बनाया। हम आपस में जुड़ी दुनिया की बात करते हैं और 2022 के बाद की घटनाओं ने हमें नए सिरे से बताया कि वैश्वीकरण के 50 वर्ष बाद हमारी अर्थव्यवस्थाएं गहराई से आपस में जुड़ गई हैं। पूरी दुनिया इनसे काफी हद तक प्रभावित हो रही है।

अमेरिकी केंद्रीय बैंक की मौद्रिक सख्ती ने दुनिया भर में नकदी की स्थिति और जोखिम वाली परिसंपत्तियों को प्रभावित किया है। भारत में यह स्टार्टअप और क्रिप्टोकरेंसी की बदली हुई दुनिया के रूप में सामने आया। यूक्रेन पर रूसी आक्रमण ने

वैश्विक ऊर्जा बाजार में बुनियादी व्यवस्था को प्रभावित किया। यूरोप जो रूसी तेल एवं गैस का सबसे अहम ग्राहक था, उसने इससे दूरी बना ली और नवीकरणीय ऊर्जा के विकास पर जोर बढ़ गया। यूरोप ने 2035 तक उत्सर्जन को विशुद्ध शून्य करने का निर्णय लिया है।

वहीं रूसी गैस तब तक यूरोपीय बाजारों में पहुंचती नहीं नजर आती है जब तक कि रूस में सत्ता परिवर्तन के बाद एक नई लोकतांत्रिक सरकार नहीं बनती। रूस को युद्ध की आर्थिक जरूरत पूरी करने के लिए तेल की अधिकतम बिक्री करना आवश्यक है। पश्चिम ने इस बिक्री पर 60 डॉलर प्रति बैरल की कीमत तय कर दी । आमतौर पर देखें तो जीवाश्म ईंधन उत्पादकों को वैश्विक स्तर पर अकार्बनीकरण का असर देखने को मिल रहा है। इन मुद्दों ने भी वैश्विक ऊर्जा कीमत के माहौल को प्रभावित किया है।

मौद्रिक नीति आर्थिक गतिविधियों को धीमा करके और मांग को कमजोर करके काम करती है। कुछ समय से ऐसा माना जा रहा था कि अमेरिकी फेडरल रिजर्व मौद्रिक सख्ती के अपने अंतिम चरण में है। परंतु 2 जून को अमेरिका में आश्चर्यजनक रूप से मजबूत रोजगार आंकड़े पेश किए गए। वहां मई में रोजगार में उल्लेखनीय इजाफा हुआ। 24 से 54 की आयु के कामकाजी प्रतिभागियों की तादाद 83.4 फीसदी बढ़ी जो काफी अधिक है। यानी फेड को मांग कम करने के लिए और कदम उठाने होंगे।

भारत में वृहद आर्थिक संदर्भ काफी अलग हैं। रिजर्व बैंक और फेड द्वारा की गई मौद्रिक नीति सख्ती ने महामारी के बाद के विस्तार को थामने में मदद की है। कई अहम संकेतक बताते हैं कि इस वर्ष वृद्धि धीमी रहेगी। शीर्ष मुद्रास्फीति में काफी गिरावट आई है और अप्रैल के ताजा आंकड़ों के मुताबिक 4.7 फीसदी रही जो चार फीसदी के लक्ष्य से केवल 70 आधार अंक अधिक है। फरवरी 2023 के बाद इजाफा रोकने की रणनीति सही राह पर है।

मुद्रास्फीति को लक्षित करने की प्रक्रिया ने भी सही काम किया है। इसके लिए रिजर्व बैंक को 12 से 18 महीने के मुद्रास्फीति लक्ष्य की घोषणा करनी होती है, अपना काम जनता के बीच लाना होता है और पूर्वानुमानों को लेकर प्रतिक्रिया देनी होती है। मुद्रास्फीति में इजाफे ने रिजर्व बैंक को और तेज कदम उठाने के लिए प्रेरित किया।

राष्ट्रीय लोकदल 2024 में किधर जायेगा

स्वदेश कुमार

पश्चिमी उत्तर प्रदेश के ताकतवर राजनैतिक घराने की तीसरी पीढ़ी इस समय अपनी सियासी साख बचाने के लिए छटपटा रहा रही है। कभी भारतीय लोकदल के बैनर तले अपनी हनक और धमक दिखाने वाले किसान नेता और पूर्व प्रधानमंत्री एवं उससे पूर्व दो बार यूपी की मुख्यमंत्री की कुर्सी पर काबिज हो चुके चौधरी चरण सिंह और उसके बाद उनके पुत्र पूर्व केन्द्रीय मंत्री अजित सिंह जिन्हें लोग छोटे चौधरी के नाम से लोग बुलाते थे कि मृत्यु के बाद जब से राष्ट्रीय लोकदल की कमान जयंत चौधरी के हाथ आई है तब से राष्ट्रीय लोकदल का वजूद संकट में आ गया है। उत्तर प्रदेश विधान सभा चुनाव में तय मानक से कम वोट प्रतिशत मिलने के कारण पार्टी की मान्यता समाप्त हो गई है, लेकिन ऐसा लगता है कि इसके बाद भी रालोद 'सियासी डिमांड' कम नहीं हुई है। करीब-करीब सभी बड़े राजनैतिक दल रालोद को अपने खेमें में लाने के लिए उत्साहित नजर आते हैं। आज भी राष्ट्रीय लोकदल सभी पार्टियों की चहेती बनी हुई है तो इसकी वजह है पश्चिमी यूपी में जाट वोटों पर उसकी दमदार पकड़। वेस्ट यूपी में जाट वोटर हमेशा निर्णायक भूमिका में रहते हैं। किसी भी राजनैतिक दल को रालोद से गठबंधन करने में परहेज नहीं रहता है तो रालोद भी मौके की नजाकत भांप कर किसी भी पार्टी के साथ समझौता करने को तैयार रहता है। ऐसा ही अगले वर्ष होने वाले आम चुनाव में भी होता दिख रहा है। आम चुनाव की सुगबुगाहट सुनाई पड़ते ही रालोद को लेकर अटकलों का बाजार गरम हो गया है। फिलहाल तो रालोद का समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन है लेकिन 2024 के आम चुनाव तक यह बना रहेगा इसकी संभावनाएं काफी कम हैं क्योंकि रालोद को इस बार सपा के मुकाबले कांग्रेस ज्यादा मुफीद नजर आ रही है। जिसके साथ वह खुलकर मोलभाव कर सकता है। वहीं बात भाजपा की कि जाए तो भाजपा के इंटरनल रिपोर्ट बात रही है कि यदि वह पूरब में ओम प्रकाश राजभर और पश्चिमी यूपी में रालोद से गठबंधन कर लेती है तो उसकी जीत की राह आसान हो सकती है। भाजपा को राजभर और जयंत चौधरी की पार्टी से गठबंधन की सूरत में सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि वह (भाजपा) जिन मुस्लिम बाहुल्य सीटों पर नहीं जीत पाती है, वहां वह पश्चिम में रालोद या पूर्वी यूपी में राजभर के सहारे अपनी नैया पार लगा सकती है। रालोद की अच्छी खासी पकड़ जाट वोटरों के अलावा मुस्लिम वोटरों पर भी है। इसके मजबूत करने के लिए रालोद आज तक अभियान भी चलाए हुए है। रालोद ने यूं तो सभी धर्मों, वर्गों को साथ जोड़ने की बात कहकर अभियान की शुरूआत की, पर इसका फोकस खास तौर से मुस्लिमों पर है। यह भविष्य को पुख्ता करने की भी कवायद है ताकि यदि लोकसभा चुनाव तक सपा से राह अलग हो तो मुस्लिम उसके साथ ही रहें। गौरतलब हो 2022 में सपा व रालोद ने विधानसभा चुनाव साथ लड़ा था। भले ही यह गठबंधन सत्ता की सीढ़ियां नहीं चढ़ पाया हो, पर रालोद को इसका खूब लाभ हुआ था। वह एक सीट से बढ़कर आठ तक पहुंच गया। बाद में खतौली उपचुनाव जीतकर संख्या नौ पहुंच गई। हाल ही में हुए नगर निकाय चुनाव में सीटों के बंटवारे को लेकर दोनों में मनमुटाव हुए तो कई जगह सपा व रालोद ने अपने अपने प्रत्याशी उतार दिए। अब रालोद के रणनीतिकारों को लग रहा है कि यदि लोकसभा चुनाव 2024 तक उनका सपा से गठबंधन टूटा तो स्थिति फिर खराब हो सकती है। ऐसे में पार्टी कोई चूक नहीं करना चाहती है। यही कारण है कि उसने 'समरसता अभियान' चला रखा है।

तीन कन्नौजिया तेरह चूल्हा वाली एकता

अनिल तिवारी

2024 के आम चुनाव की पृष्ठभूमि में देश के सारे विपक्षी दल सक्रिय हो गए हैं। भाजपा के चंद सहयोगी दलों को छोड़कर सब का एकमात्र एजेंडा बन गया है कि एन-केन-प्रकारेण भाजपा को सत्ता से अपदस्थ किया जाए। विपक्षी दलों के सामने यह छोटी नहीं बल्कि बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि ऐसा वे तभी कर सकते हैं जब वे सभी एकजुट हो जाएं, उनके पास विचारगत, नीतिगत और कार्यक्रमबद्ध साझी रणनीति हो। लेकिन इधर जो परिदृश्य दिख रहा है उसमें ऐसी संभावना लगभग क्षीण है। कांग्रेस विपक्षी एकता की धुरी बनना चाहती है, और उसकी अंतर्निहित शर्त यह है कि एकीकृत विपक्ष का नेतृत्व उसका ही हो। कांग्रेस को लग रहा है कि भारत जोड़ो यात्रा तथा अमेरिका यात्रा के बाद राहुल गांधी भाजपा के विरोधी खेमे के नेतृत्व के लिए पूरी तरह तैयार हो गए हैं। इसीलिए कांग्रेस का पहला शिकार बने नीतीश कुमार। बीते 12 जून को पटना में बुलाई गई बैठक उन्हें स्थगित करनी पड़ी। कांग्रेस ने संदेश दिया कि विपक्षी एकता की अगुवाई किसी और नेता के नेतृत्व में मंजूर नहीं है, और नीतीश कुमार भी गलतफहमी में ना रहें। विपक्षी एकता की अगुवाई कांग्रेस ही करेगी।

मालूम हो कि नीतीश कुमार अभी तक किसी ऐसे दल को विपक्षी एकता की मुहिम से जोड़ नहीं पाए हैं जो पहले से कांग्रेस के साथ न रहा हो। ममता बनर्जी, अखिलेश यादव और केजरीवाल जैसे तमाम नेता आगे क्या करेंगे, कौन सा राजनीतिक मूव लेंगे, कहा नहीं जा सकता। ऐसे में सवाल है कि एकता के प्रयास में सुशासन बाबू ने अब तक क्या पाया? इस प्रश्न का सीधा और सरल उत्तर तो यही है बैठक की एक और तारीख। तारीख पर तारीख से गुजरते हुए अब एक नई तारीख 23 जून 2023 प्रस्तावित की गई है। 23 जून की बैठक के लिए कांग्रेस के बड़े नेताओं सहित पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव, एनसीपी के शरद पवार, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन तथा भाकपा माले के नेता दीपांकर भट्टाचार्य ने अपनी सहमति दे दी है। बिहार में भाजपा को 10 से कम सीटों पर समेट देने का दावा करने वाले सुशासन बाबू अपने उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के साथ मिलकर बैठक की तैयारियों में जुटे हुए हैं।

केंद्र की वर्तमान सरकार को दिल्ली की गद्दी से उखाड़ फेंकने के नारे के साथ होने वाली मैराथन बैठक के राजनीतिक मंथन से एकता का कैसा अमृत निकलता है यह तो बैठक के बाद ही स्पष्ट होगा, लेकिन उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक, उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती और यहां तक की नीतीश कुमार के अत्यंत करीबी रहे जीतन राम मांझी ने भी बैठक के पहले ही बाय-बाय कह दिया है। अमेरिका से लौटे राहुल गांधी जरूर आत्मविश्वास से भरे नजर आ रहे हैं। अभी हाल ही में अमेरिका में उन्होंने कहा कि एकता का गणित देख लीजिए आपको समझ में आएगा। उनको पता नहीं है कि ऐसे न जाने कितने गणित कब और कैसे हवा में उड़ गए किसी को पता नहीं चला। साल 1971 में कांग्रेस विरोधी पार्टियों को भी ऐसा ही लगा था। जी-जान लगाकर विपक्ष एक हुआ था पर आंधी चली थी इंदिरा गांधी की। पिछले लोकसभा चुनाव में गणित के चक्कर में मायावती अपने राजनीतिक जीवन की सबसे बड़ी भूल कर बैठी तथा सपा को गेस्ट हाउस कांड के लिए माफ करके उससे हाथ मिला लिया। अब तक पछता रही हैं। ऐसे ही अंकगणित को देखकर ही 2019 में कांग्रेस ने कर्नाटक में जनता दल सेकुलर से गठबंधन कर लिया था। नतीजा यह हुआ कि दोनों का सफाया हो गया।

दूसरी ओर भाजपा बिजली की तेजी से आगे बढ़ रही है। आंध्र प्रदेश में जगनमोहन रेड्डी, और चंद्रबाबू नायडू दोनों उसके साथ आने को तैयार है। कर्नाटक में देवेगौड़ा की पार्टी जनता दल एस को लग रहा है कि राजनीति को बचाना है तो भाजपा के अलावा और कोई विकल्प नहीं है। बिहार में उपेंद्र कुशवाहा, पूर्वी उत्तर प्रदेश में ओमप्रकाश राजभर भाजपा के लिए एक पैर पर खड़े हैं। पंजाब में अकाली दल ने भी राजनीतिक गणित समझ लिया है कि बगैर भाजपा के सहयोग के सत्ता तक नहीं पहुंचने वाले हैं। इसलिए अब अकाली दल के नेता भाजपा की हां का इंतजार कर रहे है। सत्तारूढ़ खेमे में नेतृत्व का मुद्दा पहले से ही तय है। सीटों के बंटवारे में कोई समस्या नहीं है। विपक्षी खेमे में नेतृत्व का मुद्दा तय करने के गंभीर प्रयास किये गए तो एकता बनने से पहले टूट सकती है। सीटों का बंटवारा सबसे कठिन काम है। क्षेत्रीय दल चाहते हैं कि कांग्रेस 200 से 225 सीटों पर चुनाव लड़े और बाकी उनके लिए छोड़ दे। विपक्षी एकता (यदि कोई मूर्त रूप लेती है) की सूरत में भी कांग्रेस पार्टी कम से कम 300 सीटों पर अपना उम्मीदवार खड़ा करने का खाका तैयार कर चुकी है। वर्ष 1989 से 2014 तक के 25 साल का समय क्षेत्रीय दलों की राजनीति के लिए स्वर्ण काल था। वर्ष 2014 में भाजपा के नेतृत्व में बहुमत की सरकार बनने के बाद क्षेत्रीय दलों की भूमिका सीमित हो गई है। यदि वे कांग्रेस का सीट बंटवारे का फार्मूला मान लेते हैं तो उनकी भूमिका और सीमित हो जाएगी।

क्षेत्रीय दल इससे भलीभांति परिचित हैं। ममता बनर्जी और अखिलेश यादव पहले ही कह चुके हैं कि उनके लिए विपक्षी एकता का मतलब है बंगाल और उत्तर प्रदेश का मैदान तृणमूल कांग्रेस और सपा के लिए छोड़ दिया जाए। हालांकि नीतीश कुमार का फार्मूला है कि प्रत्येक लोकसभा सीट पर एक साझा उम्मीदवार खड़ा करने पर सहमति बन जाती है तो भाजपा को पटखनी दी जा सकती है। मौजूदा हालात को देखते हुए यह अभी दूर की कौड़ी जैसी है। वर्ष 1977 और वर्ष 1989 को छोड़ दें तो आजादी के बाद से देश में विपक्षी एकता की हर एक कवायद तीन कनौजिया तेरह चूल्हों वाली ही रही है। जितने दल उतने ज्यादा विवाद। अंत में सबकी खिचड़ी अलग ही पकती है। मालूम हो कि 2014 के बाद 2019 के लोकसभा चुनाव में भी भाजपा ने अकेले दम पर शानदार सफलता हासिल की। 2014 के मुकाबले 6.36 प्रतिशत वोट और 21 अधिक सीटें हासिल की थीं। उसे अकेले 303 और राजग को कुल 350 सीटें हासिल हुई थी। कांग्रेस को पिछले चुनाव के मुकाबले केवल 0.18त्न वोट और 8 सीटें ही अधिक मिल पाई थी। दोनों के बीच वोटों का अंतर दोगुने का था। कांग्रेस के 19.49त्न के मुकाबले भाजपा को 37.36त्न वोट प्राप्त हुए थे। इस बीच ऐसा क्या खास हो गया कि कांग्रेस के दिन बहुरने की आशा की जाए?

कृपया इनसे सीखें

जब सपना हुआ साकार

श्यामलाल

छत्तीसगढ़ के कोरिया जिले में स्थित मेरा गाँव साजा पहाड़ पथरीली जमीन से से भरा है। यह स्थिति केवल मेरे गाँव को ही नहीं, बल्कि पूरे चिरमिरी इलाके (जिस क्षेत्र में मेरा गाँव आता है) की है। पहाड़ी इलाका होने के कारण मेरे गाँव में पानी की बहुत पुरानी समस्या है। एक अदद ढंग की सड़क को तरसते मेरे गाँव से बिजली का भी कोई दूर-दूर तक रिश्ता नहीं है। यह वजह है कि गाँव वालों की प्यास बुझाने का श्रेय सदियों से गाँव के चंद कुओं को ही जाता है। ऐसे में घरेलु मवेशियों को पानी पिलाना गाँव वालों के लिए हमेशा से ही एक चुनौतीपूर्ण कार्य रहा हैं। मैंने फैसला किया कि मैं गाँव के आसपास एक तालाब बनाऊँगा। मुझे पता था कि मेरा फैसला रेगिस्तान में पानी ढूँढने वाले मुहावरे का दोहराव है और कोई भी गाँव वाला मेरे काम में मेरी मदद नहीं करेगा। उम्मीद के मुताबिक, मदद के विपरीत गाँव के दूसरे लोगों ने मेरा मजाक बनाया। मैं जब भी मवेशी चराने जाता, एक निश्चित स्थान पर खुदाई करता। इस काम को लेकर धीरे-धीरे लोग मुझे पागल समझने लगे। मैं एक प्रकार से ऐसा इंसान बन गया था, जिसे समाज ने खुद से दूर कर दिया था। मैं रोज अपने गड्ढे को बढ़ाने के लिए फावड़ा चलाता। दिन महीनों की गिनती वर्षों में होने लगी। लेकिन मुझे भरोसा था कि किसी न किसी दिन मेरी मेहनत इन्हीं वर्षों की गिनती के कारण जानी जाएगी। कुछ ऐसा ही हुआ। आखिरकार सत्ताईस साल की तपस्या के बाद मेरा सपना साकार हुआ। मेरे गड्ढे ने एक ऐसे तालाब की शक्ल ली है, जिससे पूरे गाँव की प्यास बुझ सकती है।

आज की महत्वपूर्ण घटनाएं

1915 ब्रिटिश महिला संस्थान की स्थापना हुई।
1960 रॉबर्ट बलोच के इसी नाम के एक उपन्यास पर आधारित अल्फ्रेड हिचकॉकैंड द्वारा निर्देशित थ्रिलर / हॉरर फिल्म साइको रिलीज हुई थी।
1961 पायनियरिंग रूसी बैले डांसर रुडोल्फ नुरेयेव ने फ्रांसीसी-पेरिस और पेरिस के सोशलाइट मित्र की मदद से पेरिस-ले बोरगेट हवाई अड्डे पर सोवियत संघ की रक्षा की।
1963 26 वर्षीय रूसी महिला लेफ्टिनेंट वलेंटीना तेरेशकोवा अंतरिक्ष के लिए उड़ान भरने वाली दुनिया की पहली महिला थीं।
1967 द मोंटेरे पॉप फेस्टिवल रॉक फेस्टिवल, द जिमी हेंड्रिक्स एक्सपीरियंस, थेवो और रविशंकर द्वारा प्रमुख अमेरिकी प्रदर्शनों के लिए स्थल, मॉन्टेरी, कैलिफोर्निया में शुरू हुआ।

भारतीय ज्ञान परंपरा....

गायत्रीरहस्योपनिषद् (भाग-3)

गतांक से आगे...

(वह गायत्री) अकार, उकार, मकाररूप तथा उदात्तादि (उदात्त, अनुदात्त एवं स्वरित) स्वरात्मक है। (वह त्रिकाल) संध्या के अन्तर्गत प्रातः काल के समय में हंसारूढ़ ब्राह्मीरूपा, मध्याह्न काल की संध्या में वृषभारूढ़ माहेश्वरीरूपा और अन्तिम सायंकालीन गरुडारूढ़ वैष्णवीरूपा रहती हैं। प्रातः कालीन संध्या केसमय गायत्री रक्तवर्णा, कुमारी रूपा, रक्त अंगों वाली, रक्त वस्त्रों वाली, रक्त चन्दन एवं मालाओं वाली, पाश-अंकुश-अक्षमाला कमण्डलु वरमुद्रा युक्त हाथों वाली, हंसारूढ़ा, ब्रह्मा देव शक्तिवाली, ऋग्वेद युक्ता, आदित्यपथगामिनी (आकाशगामिनी) तथा भूमण्डल पर रहने वाली हैं।

मध्याह्न काल की संध्या में (वह) सावित्री युवा, श्वेत अंगों वाली, शुभ्रवर्णा, श्वेत वस्त्रों को धारण करने वाली, श्वेतचन्दन एवं मालाएँ धारण करने वाली, त्रिशूल एवं डमरू धारण किए हुए वृषभ पर आरूढ़, रुद्राधिदेवता, यजुर्वेदयुक्ता हैं। (वह) आदित्यपथ पर गमन करने वाली और भुवः लोक में विशेष रूप से स्थित रहने वाली हैं। सायंकालीन संध्या सरस्वतीरूपा हैं। वह वृद्धा, कृष्णवर्ण वाली, कृष्ण वस्त्रों को धारण करने वाली, काले गन्धमाला का अनुलेपन करने वाली, शंख, चक्र तथा गदा धारण किये हुए, गरुड़ पर आरूढ़, विष्णु दैवत्या (विष्णु जिसका अधिदेवता है), सामवेद युक्ता, भगवान् आदित्य के पथ पर गमन करने वाली तथा स्वः अर्थात् स्वर्गलोक में निवास करने वाली हैं।

(ये गायत्री) अग्नि, वायु एवं सूर्य रूपा हैं। आहवनीय, गार्हपत्य, दक्षिणाग्नि वह्निरूपा हैं, ऋक्, यजुः तथा सामवेद स्वरूपा हैं; भूः भुवः तथा स्वः व्याहृतिरूप वाली हैं; प्रातः, मध्याह्न एवं सायंकालीन आत्मस्वरूपा; सत्त्व, रज एवं तम गुणात्मिकाः जाग्रत, स्वप्न, सुषुप्तिरूपा वसु रुद्र एवं आदित्यात्मक; गायत्री, त्रिष्टुप् एवं जगती आदि छन्दरूप वाली; ब्रह्मा, शंकर एवं विष्णु के स्वरूप वाली इच्छा, ज्ञान एवं क्रिया शक्तिरूपा तथा स्वराट्, विराट् एवं वषट् ब्रह्मरूपा हैं। (इस गायत्री महामन्त्र के) प्रथम अक्षर के अग्नि, दूसरे के प्रजापति, तीसरे के सोम (चन्द्रमा), चौथे के ईशान, पाँचवें के आदित्य, छठे के गार्हपत्य (अग्निविशेष), सातवें के मैत्र, आठवें के भाग देवता, नौवें के अर्यमा, दसवें के सविता, ग्यारहवें के त्वष्टा, बारहवें के पूषा, तेरहवें के इन्द्राग्नि, चौदहवें के वायु है।

क्रमशः...

चितरंजन दास को कैसे मिली देशबंधु की उपाधि

भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में चितरंजन दास का नाम कई योगदानों के कारण लिया जाता है। देशबंधु के नाम से मशहूर सीआर दास स्वतंत्रता सेनानी, सुप्रसिद्ध वकील, पत्रकार, कवि और राजनीतिज्ञ थे जिन्हें स्वतंत्रता आंदोलन में अपनी एक स्वतंत्र छाप छोड़ी थी और कभी भी अपने सिद्धांतों और विचारों से समझौता नहीं किया और यहां तक कि उन्होंने गांधी जी का भी विरोध किया और अंजाम की परवाह नहीं की लेकिन गांधी जी के आंदोलन के लिए सपत्नीक जेल भी जाने से नहीं हिचकिचाए। उन्हें देशबंधु की उपाधि यूं ही नहीं दी गई थी।

चितरंजन दास का जन्म 5 नवंबर 1870 को कोलकाता में वैद्य परिवार में हुआ था। वे कोलकाता उच्च न्यायलय के जाने माने वकील भुबन मोहनदास के पुत्र थे। उन्होंने कोलकत्ता के प्रेसिडेसी कॉलेज से स्नातक की पढ़ी की और फिर आईसीएस की परीक्षा भी दी जिसमें वे पास नहीं हो सके। इसके बाद उनहोने लंदन में वकालत की पढ़ाई की और फिर कोलकाता उच्च न्यायालय में वकालत शुरू की।

वकील के रूप में चितरंजन दास ने भारतीय राजनैतिक आरोपियों की पैरवी और ब्रह्माबंधाब उपाध्याय और भूपेंद्रनाथ दत्ता जैसे क्रांतिकारियों की पैरवी की जिन पर देशद्रोह का आरोप था। उन्हें साल 1908 में प्रसिद्धि मिली जब उन्होंने अलीपुर बम मामले में अरबिंदो घोष की सफल पैरवी कर उन्हें सजा से बचाया। वे क्रांतिकारियों के लिए मुकदमा तो लड़ते थे, लेकिन उनसे फीस नहीं लेते थे।

वकालत में दास सफल तो रहे लेकिन उन्हें अंग्रेज और उनका शासन बहुत नापसंद था। शुरुआत में वे बंगाल की मशहूर क्रांतिकारी संगठन अनुशीलन समिति में भी सक्रिय रहे। इसके साथ वे वकालत और पत्रकारिता भी करने लगे। 1917 में उन्होंने सक्रिय राजनीति में प्रवेश किया और वहां भी सफल रहे, लकिन उनका राजनैतिक सफल कम समय तक रहा।

उस समय के तिकड़ी लाल बाल पाल में से दास बिपिन चंद्र पाल के बहुत ही करीबी थे। उन्होंने एनी बेसेंट को कांग्रेस अध्यक्ष बनवाने में अहम भूमिका निभाई। दास स्वदेशी के विचार से बहुत ज्यादा प्रभावित थे। उन्होंने बंगाल में गांवों के पुनर्निर्माण , स्थानीय स्वशासन की स्थापना, और कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए काम किया।

1920 गांधी जी की असहयोग आंदोलन में भी दास ने सक्रियता दिखाई। उन्हें अपनी आलीशान जीवनशैली छोड़ खादी को अपनाया और बंगाल में कई जगह ब्रिटिश कपड़ों का बहिष्कार किया। इस दौरान वे अपनी पत्नी और बेटे के साथ छह महीने के लिए जेल भी गए थे। उसी साल उन्हें अहमदाबाद अधिवेशन में कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया। खादी अपनाते समय ही दास ने अपने सारी संपत्ति एक मेडिकल कॉलेज के नाम दान कर दी और देशसेवा में अपने जीवन के अंतिम समय तक लगे रहे। उनके इस त्याग और देशभक्ति के चलते ही उन्होंने देशबंधु कहा जाने लगा था। अपने जीवन के अंतिम समय में उन्हें स्वास्थ्य का साथ नहीं मिला और 16 जून 1925 को बीमारी की वजह से उनक निधन हो गया।

सभी के लिए किफायती स्वास्थ्य सेवा

डॉ. नरेश त्रेहन

स्वास्थ्य वास्तव में एक आवश्यक स्तंभ है। यह वाक्य यह रेखांकित करता है कि अगले 25 वर्षों में भारत की विकास यात्रा पर विचार करें तो सरकार और निजी स्वास्थ्य सेवा के दिग्गजों को किस विषय पर अपना ध्यान केंद्रित करना चाहिए, जिससे दुनिया का सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश भारत, विश्व के सबसे समृद्ध देश के रूप में प्रतिस्थापित हो सके। देश में रोग और मृत्यु दर में कमी लाई जा सके और 1.43 बिलियन लोगों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए गुणवत्तापूर्ण और किफायती स्वास्थ्य सेवाएं समय पर उपलब्ध कराई जा सकें।

किसी व्यक्ति के अच्छे स्वास्थ्य, धनोपार्जन की क्षमता और देश की आर्थिक समृद्धि के बीच संबंध को नकार नहीं सकते है। भारत, समान विकास पर आधारित 25 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने के लिए कार्यशील है, बदलती जनसांख्यिकी, जीवन शैली, बदलते वायरस, कोविड-19 जैसी महामारियों और जलवायु संकट से उत्पन्न स्वास्थ्य चुनौतियों से निपटने के लिए उसे एक बहु-आयामी दृष्टिकोण अपनाना होगा। भारत को स्वास्थ्य के क्षेत्र की पारंपरिक चुनौतियों जैसे अंतर-राज्य और शहरी-ग्रामीण असमानताओं, रोगियों की तुलना में स्वास्थ्य कर्मियों की कमी और टियर-1, 2 और 3 शहरों में अस्पताल सेवाओं में कमी के अंतराल से निपटने के तरीके भी तलाशने होंगे। इस संदर्भ में, सस्ती स्वास्थ्य सेवा तक सभी की पहुंच बना कर, भारत प्रतिष्ठा के एक नए आयाम तक पहुंच सकता है। इस दिशा में, भारत ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति, 2017 के

अंतर्गत नई योजनाओं के साथ स्वास्थ्य सेवा और उपलब्धता सुधारने में काफी प्रगति की है। सरकार ने डिजिटल स्वास्थ्य प्रौद्योगिकी पर विशेष ध्यान देने और उसे बढ़ावा देने के उद्देश्य से और स्वास्थ्य सेवाओं को कोने कोने तक ले जाने के उद्देश्य से इन योजनाओं का शुभारंभ किया गया है।

उदाहरण के लिए, 1.5 लाख से अधिक आयुष्मान भारत स्वास्थ्य और वैलनेस केंद्रों की स्थापना की गई है और 700 से अधिक जिलों में 9,000 से अधिक जन औषधि केंद्रों का एक नेटवर्क तैयार किया गया है जिनमें गुणवत्ता पूर्ण जेनेरिक दवाएं रखी गईं हैं। लेकिन सार्वभौमिक स्वास्थ्य सेवाओं की कवरेज सुनिश्चित करने की दिशा में सर्वाधिक महत्वपूर्ण पहल आयुष्मान भारत पीएम-जन आरोग्य योजना है। इसमें भारत के सर्वाधिक 40 प्रतिशत गरीब लोगों सहित लगभग 55 करोड़ लोगों को प्रति वर्ष प्रति परिवार 5 लाख रुपये की राशि अस्पताल के खर्च को पूरा करने के लिए दी जाती है। निजी क्षेत्र द्वारा समर्थित, यह योजना सुनिश्चित करती है कि अत्याधुनिक उपचार की जरूरत वाले रोगी इससे लाभान्वित हो सकें।

भले ही हमने कोविड-19 महामारी से निजात पाई हो लेकिन स्वास्थ्य सेवाओं के अतिरिक्त बोझ का डर हमें परेशान करता रहेगा। लंबे समय तक कोविड की स्थिति, गैर-संचारी रोगों में वृद्धि, उपचार में देरी और कोविड के कारण बिगड़ती स्वास्थ्य स्थिति - ये सभी कारक निकट भविष्य में आर्थिक बोझ का कारण बनने की संभावना रखते हैं। यह विशेष रूप से चिंताजनक है क्योंकि हमारी आबादी का एक बड़ा हिस्सा अभी भी गांवों में रहता है, जहां प्राथमिक और माध्यमिक स्वास्थ्य केंद्रों के नेटवर्क, मेडिकल कॉलेजों और उनकी सीटों में वृद्धि के बावजूद, डॉक्टर और रोगी के बीच का अनुपात पर अभी काम चल रहा है।

भारत में डिजिटल नवाचार - महामारी की शुरुआत से बहुत पहले से ही स्वास्थ्य सेवाओं में मददगार रहे हैं। सरकार के टेलीमेडिसिन ऐप ई-संजीवनी ने विशेषज्ञ डॉक्टरों से परामर्श करने की दूरी को समाप्त कर दिया है और शहरी-ग्रामीण विभाजन को पाट दिया है। अपने लॉन्च के तीन साल से भी कम समय में, इसने 10 करोड़ से अधिक लोगों की मदद की है। निजी क्षेत्र ने भी अंतिम छोर की खाई को पाटने और स्वास्थ्य सेवाओं की कमी को मिटाने के लिए कई पहल की हैं। टेलीमेडिसिन के अतिरिक्त, इसका उपयोग दूर-दराज के क्षेत्रों में रोगियों को स्वास्थ्य संबंधी परामर्श उपलब्ध कराने और उनके उपचार की देखरेख करने में किया जा रहा है। बड़े पैमाने पर स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं ने दूरस्थ महत्वपूर्ण देखभाल सेवाएं (ई-आईसीयू) भी शुरू की हैं। नेशनल हेल्थ स्टैक और नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन जैसी सरकारी पहलों ने एक एकीकृत और निर्बाध स्वास्थ्य सेवा वितरण प्रणाली के विकास के लिए मजबूत नींव बनाई है जो तृतीयक देखभाल प्रदाताओं को प्रभावी, कुशल और व्यक्तिगत स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने में मदद करती है। स्मार्टफोन उपयोगकर्ताओं की बढ़ती संख्या और डिजिटल स्वास्थ्य प्रणाली को सक्रिय रूप से अपनाने के साथ, वंचित और हाशिए वाले समुदायों के बीच कम लागत पर स्वास्थ्य देखभाल उपलब्धता और गुणवत्ता में असमानताओं को कम कर रहे हैं। ये रोग की रोकथाम और प्रारंभिक लक्षणों को पहचाने में सक्षम हैं। यह उपकरण बीमारी के दीर्घकालिक बोझ और लागत को कम करने में मदद कर सकते हैं और आबादी के समग्र कल्याण में बेहतर योगदान दे सकते हैं।

इसके अतिरिक्त, डिजिटल स्वास्थ्य समाधान बड़े पैमाने पर डेटा संग्रह और विश्लेषण करने में मददगार हो सकते हैं, जिससे यह जन स्वास्थ्य उपायों और नीतियों के बारे में जानकारी उपलब्ध करा सकते हैं। यह सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं को रोग नियंत्रण, प्रकोप प्रबंधन और स्वास्थ्य संवर्धन के लिए साक्ष्य-आधारित रणनीतियों को विकसित करने में सक्षम बना सकते हैं। उदाहरण के लिए, इनसे रोगों की स्थिति पर नज़र रखने में मदद मिल सकती है, जिससे उभरते स्वास्थ्य जोखिमों की पहचान में सहायता और उचित तकनीक विकसित करने में मदद मिल सकती है। सरकारी कार्यक्रम और निजी स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र की संलग्नता और डिजिटल स्वास्थ्य समाधान मिलकर सबके लिए सस्ती स्वास्थ्य देखभाल को पुनर्परिभाषित करते हैं ताकि एक समन्वित प्रणाली प्रस्तुत कर सके।

बापू की दिनचर्या

दिन का भोजन (भाग-5)

गतांक से आगे...

नमक को बापू पाचन शक्ति बढ़ानेवाली वस्तु नहीं मानते। हाँ, बालकों की हड्डी के विकास के लिए नमक उनकी दृष्टि में आवश्यक था। तीस वर्ष की उम्र तक उसका सेवन लाभप्रद और उसके बाद हानिप्रद अन्यथा अनावश्यक है, ऐसा उनका विचार था। सन् 1908 में बापू के नमक छोड़ने का प्रसंग फिनिक्स (दक्षिण अफ्रीका) का है। उन दिनों इस विषय पर उनका अन्वेषण आरंभ हो गया था । राष्ट्रमाता कस्तूरबा अस्वस्थ थीं। उन्हें नश्तर लगा था। बाद में उनका रक्तस्राव पुनः शुरू हो गया और वह असाध्य-सा प्रतीत होने लगा। कई प्रयोग विफल हो चुके थे। इस पर बापू ने उनको नमक तथा दाल का त्याग करने का परामर्श दिया। काफी समझाने पर भी बा इसके लिए राजी न हुई। उन्होंने स्वयं बापू के लिए ऐसा करना असंभव बताया। बापू ने उनकी धारणा को गलत सिद्ध करते हुए उसी दिन से एक वर्ष के लिए नमक छोड़ने का संकल्प किया। बाद में बा ने ये दोनों वस्तुएँ छोड़ने की प्रतिज्ञा करते हुए बापू से अपनी प्रतिज्ञा वापस लेने का आग्रह किया, किंतु वे तनिक विचलित न हुए। सूर्य का पश्चिम में उदय होना भले ही संभव हो, किंतु वे अपनी प्रतिज्ञा तोड़नेवाले नहीं थे। उन्होंने कहा कि किसी भी निमित्त से पाला गया संयम लाभप्रद ही होता है। नमक छोड़ने से बा के स्वास्थ्य में अत्यधिक सुधार हुआ। छोड़ देने के बाद नमक या दाल ग्रहण करने की बापू की इच्छा तक न रही। कभी-कभी वे नमक ले लेते। उन्होंने सदा के लिए नमक छोड़ने की प्रतिज्ञा भी नहीं की थी। उन्होंने सन् % 33 में एक बार कहा था कि नमक ग्रहण करने की लालसा मन में रहती हो, ऐसा नहीं, बल्कि खाने पर अच्छा लगता है; लेकिन जिस क्षण उन्हें ज्ञात हो जाता कि अमुक वस्तु उनके लिए हानिकारक है, उसी क्षण वे उसे त्याग देते। बापू, जीभ और आँख की उपमा श्वान से देते। मन को मदिरा पान किए बंदर की दी जानेवाली उपमा को वे ठीक बताते। इसी कारण वे कभी अपने मन के गुलाम नहीं बने।

क्रमशः ...

संक्षिप्त समाचार

एक शाम अखिल के नाम 17 को

रायपुर। एक शाम अखिल सचदेवा के नाम का आयोजन 17 जून को होगा। इसमें नवोदित संगीत कलाकार अखिल सचदेवा अपनी टीम के साथ प्रस्तुति देंगे। वे इन दिनों भारत भ्रमण पर निकले हैं। कार्यक्रम सेरेखेड़ी स्थित ललित महल में होगा। लाइव कंसर्ट के आयोजक वीनस एंटरटेनमेंट है। उल्लेखनीय है कि अखिल सचदेवा ने 2017 में हम्प्टी शर्मा की दुल्हनिया के सुप्रसिद्ध ट्रैक सुन मेरे हमसफ़र के साथ अपने करियर को पहचान दी। उन्होंने चन्ना तेरे नाल करना प्यार वे, मैं तेरा बन जाऊंगा, आदि अखिल के गए हुए प्रसिद्ध गाने हैं। इस कार्यक्रम में स्थानीय कलाकार सत्यम, योगेश, ओंकार, कार्तिक, अगस्टाइन और आदित्य भी परफॉर्म करेंगे।

कई आरक्षक हुए इधर-उधर

राजनांदगांव। प्रशासनिक दृष्टिकोण के लिहाज से एसएसपी अभिषेक मीणा ने पुलिस विभाग में कई आरक्षकों का तबादला आदेश जारी किया। डोंगरगढ़ के मौजूदा थाना प्रभारी एमन साहू को राजनांदगांव कोतवाली का नया प्रभार सौंपा गया है। वहीं उनकी जगह डोंगरगढ़ में रामअवतार ध्रुव को थाना का जिम्मा मिला है। एमन साहू को कुछ माह पूर्व ही डोंगरगढ़ में बतौर थाना प्रभारी भेजा गया था। इसके अलावा निरीक्षक रामेन्द्र सिंह को बागघनदी से रक्षित केंद्र, निरीक्षक संतोष ठाकुर को रक्षित केंद्र से बोरतलाव, निरीक्षक मनीष धुर्वे को रक्षित केंद्र से बागनदी थाना प्रभारी की जिम्मेदारी दी गई है। इसी तरह निरीक्षक बसंत बघेल को जिला विशेष शाखा से चिखली चौकी प्रभारी, निरीक्षक उमेश बघेल को चिचोला चौकी व निरीक्षक शैलेन्द्र सिंह ठाकुर को चिखली से जिला विशेष शाखा का प्रभारी बनाया गया है। एसआई पवन पटेल को रक्षित केंद्र से कोतवाली, एसआई नारायण ठाकुर को रक्षित केंद्र से बसंतपुर, एसआई हेमवंत चंद्राकर को बसंतपुर से प्रभारी सुरगी चौकी बनाया गया। वहीं एएसआई इसराफिल खान को यातायात शाखा, एएसआई संतोष सिंह को सायबर सेल, एएसआई सुमन कर्ष को डोंगरगांव से डीआरजी, एएसआई अश्वनी यदु को बोरतलाव से डीआरजी में पदस्थ किया गया है।

डॉ. संगीता ने कराया 89 वर्षीय महिला का भाजपा की सदस्यता का नवीनीकरण

भिलाई। पीएम नरेन्द्र मोदी के विकास कार्यों से प्रभावित होकर 89 वर्षीया नारी शक्ति स्वरूपा प्रमिला नायर ने कराया भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता का नवीनीकरण। इस दौरान प्रमिला ने बीजेपी की सक्रिय सदस्य व सिम्प्लेक्स कास्टिंग लिमिटेड की एमडी डॉ संगीता शाह से संपर्क कर सदस्यता नवीनीकरण की इच्छा जताई। तब डॉ संगीता शाह ने अपने साथी कार्यकर्ताओ के साथ उनके निवास पहुची और स उनकी सदस्यता का नवीनीकरण कराया। प्रमिला नायर भिलाई स्टील प्लांट, कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट में पहली इंजीनियर महिला कर्मचारी के रूप में 1957 को कार्यरत थी। 1992 में नौकरी से सेवानिवृत्त होने के बाद उन्होंने गरीब परिवारों के बच्चों को पढ़ाने की जिम्मेदारी उठाई और समाज में एक मिसाल कायम की। इस अवसर पर प्रमिला को उनका सदस्यता कार्ड और प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ। प्रमिला नायर ने कहा कि मैं अपने राष्ट्र की प्रगति में सक्रिय रूप से शामिल होने पर जोर देना चाहती हूं। हमारे नेता नरेंद्र मोदी द्वारा निर्धारित, सिद्धांतों का पालन करने ,और योगदान करने के लिए प्रोत्साहित करती हूं। हमारे राष्ट्र को ऐसे समर्पित व्यक्तियों की आवश्यकता है ,जो सकारात्मक बदलाव लाने के लिए प्रयास करने को तैयार हों। प्रधान मंत्री मोदी ने शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल और बुनियादी ढांचे जैसी विभिन्न योजनाओं की शुरुआत की है। इसलिए प्यारे नौजवानों, राष्ट्र के बारे में सोचो, राष्ट्र के हित में काम करो और बेहतर भारत की यात्रा में शामिल होकर आने वाली पीढ़ियों के लिए एक समृद्ध भविष्य बनाने में मदद करो।

बिलासपुर रेलवे स्टेशन के नजदीक 100 गुमटियों में लगी भीषण आग

बिलासपुर। रेलवे परिक्षेत्र के बुधवारी बाजार की गुमटियों में भीषण आग लग गई है. घटना की जानकारी मिलते ही दमकल की टीम और पुलिस के साथ जिला प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची. बड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया है. पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। जानकारी के अनुसार, आग की चपेट में आने से 100 गुमटियां जलकर खाक हो गई है. जिससे लाखों का नुकसान हुआ है. हालांकि, आग लगने का कारण अब तक पता नहीं चल पाया है. तोरवा पुलिस मामले की जांच कर रही है।

ट्रेनों की लेटलतीफी से नाराज दैनिक यात्रियों ने सरोना में किया हंगामा

रायपुर। ट्रेनों की लेटलतीफी अब यात्रियों को रास नहीं आ रही है। खासकर दैनिक यात्रा करने वाले यात्री इससे बेहाल हो गए हैं। इसी तरह आज लोकल ट्रेन के लेट होने पर तथा बेवजह रोके जाने से नाराज दैनिक यात्रियों ने सरोना में जमकर हंगामा किया। सूत्रों की माने तो डोंगरगढ़, राजनांदगांव, दुर्ग, भिलाई से लेकर बिलासपुर तक के दैनिक यात्री रोजाना लोकल ट्रेन से रायपुर, बिलासपुर आते-जाते हैं। वर्तमान में घंटों विलंब से चल रहे ट्रेनों की वजह से इनका कामकाज बुरी तरह से प्रभावित होता है। भाटापारा और तिल्दा जैसे इलाके से रोजाना हजारों व्यापारी रायपुर और बिलासपुर आते-जाते हैं। इसके अलावा राजनांदगांव तक से लोग काम के लिए रोजाना राजधानी रायपुर आते हैं। विलंब से चल रहे ट्रेनों के चलते इनका कामकाज बुरी तरह से प्रभावित होता है। इसके अलावा ट्रेनों को सिग्नल न मिलने के कारण भी कई स्टेशनों में अथवा आउटर में खड़ा कर दिया जाता है।

तेलंगाना के किसानों ने प्रदेश में संचालित योजनाओं को सराहा : बघेल

तेलंगाना के 500 किसानों ने की मुलाकात, छत्तीसगढ़ के गौठानों के भ्रमण के बाद साझा किए अपने अनुभव

रायपुर। छत्तीसगढ़ का विकास मॉडल देखने आए तेलंगाना के किसानों ने छत्तीसगढ़ में संचालित किसान हितैषी नीतियों और योजनाओं को सराहा। तेलंगाना के विभिन्न जिलों से आए 500 किसानों ने राजनांदगांव और दुर्ग जिले में छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा संचालित की जा रही किसान हितैषी योजनाओं का अवलोकन करने के बाद आज सवेरे मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल से उनके निवास में प्रदेश के मुखिया श्री बघेल से अपने अनुभव साझा किए। कार्यक्रम की शुरुआत करते हुए तेलंगाना से आए किसान प्रतिनिधियों ने पारम्परिक वस्त्र गोंगड़ी पहनाकर और बैलगाड़ी का मॉडल भेंट कर मुख्यमंत्री का स्वागत एवं अभिनंदन किया।

तेलंगाना के किसानों ने इसके पहले राजनांदगाव जिले के डोंगरगांव विकासखण्ड के अमलीडीह गौठान और दुर्ग जिले के पुलगांव गौठान का अवलोकन किया और छत्तीसगढ़ के किसानों, मजदूरों और गौपालकों से चर्चा कर योजनाओं की विस्तृत जानकारी ली। छत्तीसगढ़ सरकार की योजनाओं और नीतियों की तारीफ करते हुए तेलंगाना के किसान प्रतिनिधि श्री शरद कुमार ने कहा छत्तीसगढ़ सरकार आम जनता और किसानों के हित में महत्वपूर्ण योजनाएं संचालित कर रही हैं और इनका लाभ भी आम जनता को मिल रहा है। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल के नेतृत्व की सरकार ने महात्मा गाँधी की ग्राम स्वराज की कल्पना को साकार किया है। धान का बेहतर मूल्य, गोबर की खरीदी, जैविक खेती को प्रोत्साहन मिलने से यहां के किसानों के चेहरे पर खुशी दिख रही है। श्री शरद कुमार ने कहा कि भूपेश सरकार का यह किसान मॉडल पूरे देश में भी लागू किया जाना चाहिए। श्री शरद कुमार ने प्रदेश सरकार द्वारा संचालित की जा रही योजनाओं की तारीफ करते हुए कहा कि किसान हितैषी योजनाओं से न केवल किसान समृद्ध हो रहे हैं, बल्कि बेहतर आजीविका भी सुनिश्चित हो रही है और इस पूरे मॉडल को समझने के लिए तेलंगाना से हम सभी किसान छत्तीसगढ़ आए हैं।

तेलंगाना से आए किसान श्री एम. शिवा वीर रेड्डी ने कहा आपकी सरकार प्रदेश के किसानों के लिए बढ़िया काम कर रही है। गोबर खरीदी योजना से पूरे देश में आपकी पहचान गोबर खरीदने वाले मुख्यमंत्री के रूप में बनी है। श्री स्वामी ने कहा कि मैं स्वयं गोपालन करता हूं यदि आप जैसी योजनाएं हमारे भी प्रदेश में भी संचालित होती तो मैं एक सौ नहीं हजार गाय पालता। श्री स्वामी ने कहा कि छत्तीसगढ़ में गौठान, गोपालन तथा किसानों के हित में संचालित की जा रही योजनाओं का, मीडिया के जरिए पूरे देश में प्रचार-प्रसार होना चाहिए ताकि अन्य प्रदेश के किसानों को भी इसकी जानकारी मिल सके।

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा हमारी सरकार किसानों की सरकार है और किसानों की खुशहाली और समृद्धि के लिए हम संकल्पित हैं। उन्होंने कहा कि पिछली सरकार में केवल 12 लाख किसान प्राथमिक सहकारी सोसाइटी में धान बेचते थे परंतु आज 23 लाख से अधिक किसान सोसाइटी में धान बेच रहे हैं और पैसा तत्काल उनके खातों में पहुँच रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राजीव गांधी किसान न्याय योजना से अब तक 26 लाख से अधिक किसान लाभान्वित हो चुके हैं, देश में धान का सर्वाधिक मूल्य छत्तीसगढ़ के किसानों को एम.एस.पी. और इन्पुट सब्सिडी मिलाकर मिल रहा है। मुख्यमंत्री श्री बघेल ने कहा कि इस वर्ष साढ़े 23 लाख किसानों से 107 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी की गई है। अभी तक हम किसानों से 15 क्विंटल प्रति एकड़ धान की खरीदी कर रहे थे, अब 20 क्विंटल प्रति एकड़ धान की समर्थन मूल्य पर खरीदी की जाएगी। हमारी सरकार 67 प्रकार के लघु वनोपजों की खरीदी कर रही है और उनका वैल्यू एडिशन कर सी मार्ट के जरिए बिक्री भी की जा रही है। गोबर खरीदी योजना से यहां के किसान गोबर बेच कर लखपति बन रहे हैं। मुख्यमंत्री श्री बघेल ने कहा हमारे यहां न केवल गोबर से पेंट का निर्माण किया जा रहा है बल्कि गोबर से बिजली उत्पादन को भी हम प्रोत्साहन दे रहे हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि धान से एथेनॉल बनाने के लिए अनुमति देने के संबंध में हमने प्रधानमंत्री जी को पत्र लिखा है यदि अनुमति मिलती है तो प्रदेश के किसानों को धान का और भी ज्यादा मूल्य प्राप्त होगा। प्रदेश में आदिवासियों के लिए चल रही योजनाओं के प्रश्न पर जवाब देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार आदिवासियों और वनवासियों के हितों के प्रति पूरी तरह संवेदनशील है। लघु वनोपजों के समर्थन मूल्य पर खरीदी, वनोत्पाद आधारित आजीविका गतिविधि तथा वन अधिकार पट्टा प्रदान कर सरकार आदिवासियों के जीवन में खुशहाली लाने का कार्य कर रही है। मुख्यमंत्री श्री बघेल ने कहा कि वन अधिकार पट्टा योजना के जरिए 5 लाख किसानों व्यक्तिगत वन अधिकार पट्टे दिये गए है इसी तरह सामुदायिक वन अधिकार 18 लाख हेक्टेयर से अधिक जमीन पर आदिवासियों एवं पात्र हितग्राहियों को प्रदान किया जा चुका है। इसमें वन संसाधन अधिकार भी शामिल हैं।

प्रदेश में बढ़ते क्राइम पर लगेगी लगाम, गृहमंत्री ने ली समीक्षा बैठक, दिए कई अहम निर्देश

रायपुर। छत्तीसगढ़ में अब क्राइम पर लगाम लगेगी। राज्य सरकार इस मामले में काफी गंभीर है। इस संबंध में प्रदेश के गृहमंत्री ताम्रध्वज साहू ने बेमेतरा प्रवास के दौरान जिला कार्यालय कलेक्टोरेट के दिशा-सभाकक्ष में गृह विभाग के अधिकारियों की अपराध एवं कानून व्यवस्था के संबंध में समीक्षा बैठक ली। बैठक में गृहमंत्री ताम्रध्वज साहू ने पुलिस अधीक्षक भावना गुप्ता से जिले के थाना, परिसीमन, चौकी, लाइन, बल की उपलब्धता और सुरक्षा संबंधित अन्य विषयों की जानकारी ली। बैठक के दौरान पुलिस अधीक्षक ने जिले में चल रहे कानून व्यवस्था और घटनाओं के बारे में विस्तार से चर्चा की।

गृह मंत्री साहू ने पुलिस अधीक्षक को सीमा क्षेत्रों पर विशेष निगरानी रखते हुए जिले के आंतरिक क्षेत्रों में भी निगरानी रखे जाने के निर्देश दिए। उन्होंने जिले में अपराधिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए सुरक्षा व्यवस्था को और अधिक मजबूत करने के निर्देश दिए। पुलिस अधीक्षक को जिले में सुरक्षा बल की और आवश्यकता होने पर जानकारी भेजने को कहा। उन्होंने जिले में आक्रामक भाषण और सामाजिक माहौल खराब करने वालों पर अनुशासनात्मक कार्यवाही करने को कहा एवं जिले में साइबर केस के संबंध में जानकारी ली और साइबर क्राइम के थानों पर अत्याधुनिक उपकरण की व्यवस्था करने को कहा एवं महिला अपराध जैसे विषयों पर भी चर्चा की गई।

गृहमंत्री साहू ने महिलओं और बच्चों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देने को कहा और जिले में हुक्का, नशीले पदार्थों पर लगातार मॉनिटरिंग करते हुए प्रभावकारी कदम उठाने के निर्देश दिए। गृहमंत्री ने सोशल मीडिया के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए कहा कि इन सब के कारण पुलिस की चुनौतियां बढ़ गई है ऑनलाइन ठगी के मामले बढ़ते जा रहे हैं। इस तरह के उन्माद फैलाने वाली सुचनाओं के भ्रामक प्रचार को रोकना भी जरुरी हो गया है। इसके लिए पुलिस को और सक्रियता बढ़ाकर सकारात्मक प्रयास करने के निर्देश दिए।

लोक निर्माण मंत्री ताम्रध्वज साहू ने गत बुधवार को बेमेतरा जिले के एक दिवसीय प्रवास के दौरान जिला कार्यालय के सभाकक्ष में लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों की बैठक लेकर जिले में चल रहे निर्माण कार्यों की प्रगति की जानकारी ली। उन्होंने 2023-24 के बजट में सम्मिलित सड़क निर्माण कार्य के तहत पूर्ण, अपूर्ण, और प्रगतिरत निर्माण कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने बजट एवं प्रथम, द्वितीय, तृतीय अनुपूरक बजट में सम्मिलित कार्यों की प्राक्कलन की स्थिति की जानकारी ली। लोक निर्माण मंत्री ने जिले के निर्माणाधीन निर्माण कार्यों को गुणवत्ता पूर्ण तरीके से एवं समय सीमा में पूरा करने के निर्देश अधिकारियों को दिए। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि इन कार्यों में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इसके साथ ही श्री साहू ने लोक निर्माण विभाग अंतर्गत ई-श्रेणी पंजीयन, प्रगतिरत कार्य, दिए गए कार्यों इत्यादि विषयों पर विस्तार से चर्चा की और आवश्यक दिशा निर्देश दिए।

मुख्यमंत्री भूपेश 19 को जीपीएम दौरे पर

विकास कार्यों का लोकार्पण और इंदिरा गांधी राजीव गांधी की प्रतिमा का करेंगे अनावरण

गौरेला-पेंड्रा-मरवाही। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल 19 जून को गौरेला-पेंड्रा-मरवाही जिले के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वे नगर पंचायत पेंड्रा के विद्यानगर में नवनिर्मित माधव राव सप्रे प्रेस क्लब का उद्घाटन करेंगे। साथ ही इंदिरा गांधी और राजीव गांधी की प्रतिमा भी अनावरण करेगे। इसके अलावा कई विकास कार्यों का भी लोकार्पण होगा। मुख्यमंत्री बघेल के दौरे को देखते हुए प्रशासन तैयारियों में लगा है। इसे लेकर गुरुवार को कलेक्टर और एसपी ने कार्यक्रम स्थलों का निरीक्षण किया।

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल प्रेस क्लब के पीछे विकासित किए गए गार्डन में पंडित माधव राव सप्रे जी की मूर्ति का अनावरण करेंगे। इसके साथ ही पेंड्रा में पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और राजीव गांधी की मूर्ति का अनावरण करेंगे। मुख्यमंत्री प्रेस क्लब पेंड्रा के पास आम सभा में विभिन्न विकास कार्यो का लोकार्पण, भूमिपूजन एवं हितग्राही मूलक योजनाओं के तहत सामग्री वितरण करेंगे। इसके अलावा सुप्रसिद्ध साहित्यकार पंडित माधव राव सप्रे की 152वीं जयंती के उपलक्ष्य में मां कल्याणिका पब्लिक स्कूल गौरेला में आयोजित सप्रे स्मृति महोत्सव में भी शामिल होंगे।

जिला कलेक्टर प्रियंका ऋषि महोबिया और पुलिस अधीक्षक योगेश पटेल ने मुख्यमंत्री के प्रस्तावित दौर की तैयारियों के तहत स्थल निरीक्षण किया। उन्होंने मल्टीपर्पज शाला मैदान में निर्मित स्थायी हैलीपैड का निरीक्षण कर वहां आस पास साफ-सफाई, बैरीकेट, पार्किंग तथा सुरक्षा व्यवस्था आदि के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए। कलेक्टर ने नवनिर्मित प्रेस क्लब का अवलोकन किया और वहां एसी, फर्नीचर एवं विद्युत कनेक्शन जोड़ने के निर्देश दिए।

मुख्यमंत्री ने देशबंधु चितरंजन दास की पुण्यतिथि पर किया नमन

रायपुर। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और प्रसिद्ध विधि-शास्त्री श्री चितरंजन दास की पुण्यतिथि 16 जून को उन्हें नमन किया है। श्री बघेल ने कहा है कि श्री चितरंजन दास ने राष्ट्रसेवा में अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया। वे अपनी तीक्ष्ण बुद्धि के लिए जाने जाते हैं।

सड़क किनारे अवैध शराब बिक्री से राहगीर हलाकान

रायपुर। मंदिर हसौद थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले एक व्यस्त सड़क मार्ग के ग्राम सोनपैरी व बड़गांव में खुले आम अवैध शराब बिक्री से राहगीर परेशान व हलाकान हो चले हैं । इस मार्ग से गुजरने वाले प्रबुद्ध व जागरूक ग्रामीणों द्वारा लगातार कराये जा रहे ध्यानाकर्षण पर क्षेत्र में शराब विरोधी मुहिम में सक्रिय किसान संघर्ष समिति के संयोजक भूपेन्द्र शर्मा ने इन दोनों ग्रामों के सरपंच को पत्र लिख न केवल राहगीरों के वरन् ग्रामहित में भी ग्रामीण व्यवस्था के तहत अथवा पुलिस प्रशासन के सहयोग से इस पर स्थायी रोक लगाने त्वरित पहल का अनुरोध किया है । साथ ही मंदिर हसौद थाना प्रभारी विरेन्द्र चंद्रा को इसकी प्रति भेज राहगीरों को अवांछनीय हरकतों से निजात दिलाने त्वरित ठोस स्थायी कार्यवाही का आग्रह किया है ।

छतौन-दरबा-टेकारी-नारा-लखौली सड़क मार्ग पर पड़ता है ग्राम सोनपैरी व बड़गांव । लगभग 25- 30 ग्रामों के ग्रामीण दिन रात इस सड़क मार्ग से गुजरते हैं । इन दोनों ग्रामों के बीच की दूरी बमुश्किल 5-6 किलोमीटर है पर इन दोनों ग्रामों में शराब बिक्री की वजह से अघोषित भट्ठी का माहौल बना रहता है । पहले इन दोनों ग्रामों के बीच पड़ने वाले ग्राम कुटेसर में भी सड़क किनारे अघोषित भट्ठी का माहौल बना रहता था पर राहगीरों सहित श्री शर्मा के सक्रियता व थाना अमला के दबिश के चलते फिलहाल इस ग्राम में सड़क किनारे अवैध शराब बिक्री थमा हुआ है लेकिन सोनपैरी व बड़गांव में स्थिति बेहाल है । खासकर शाम ढले तो इन दोनों ग्रामों में भट्ठी जैसे माहौल रहता है । इसकी वजह से जहां हरहमेशा दुर्घटना का अंदेशा बना रहता है वहीं राहगीरों को भी अशोभनीय हरकतों से साक्षात्कार करना पड़ता है । इस संबंध में प्रभावित व पीड़ित ग्रामों के ग्रामीणों द्वारा समय - समय पर पंचायत प्रतिनिधियों व थाना प्रशासन का ध्यानाकर्षण कराया जा चुका है पर अब तक किया गया पुलिसिया कार्यवाही प्रभावी साबित नहीं हुआ है । राहगीरों से मिल रहे लगातार शिकायतों को दृष्टिगत रखते हुये श्री शर्मा ने सोनपैरी के सरपंच हरगुन गायकवाड़ व? बड़गांव के सरपंच श्रीमती रामबती मुरारी यादव का ध्यानाकर्षण इस ओर कराते हुये ग्रामीण व्यवस्था के तहत शिकंजा कस अवैध शराब बिक्री पर रोक लगाने व इसकी अवहेलना करने पर पुलिस प्रशासन का सहयोग ले इस पर सख्ती से रोक लगाने त्वरित पहल का आग्रह किया है ।

प्रतिभावान खिलाड़ियों का उद्योग मंत्री, सांसद और विधायकों ने किया सम्मान

■ **खेलो इंडिया के तहत आयोजित आदिवासी नेशनल टूर्नामेंट में बस्तर के खिलाड़ी रहे छत्तीसगढ़ टीम का हिस्सा**

जगदलपुर। खेलो इंडिया के तहत आयोजित आदिवासी नेशनल टूर्नामेंट में बस्तर की प्रतिभावान खिलाड़ी छत्तीसगढ़ की टीम का हिस्सा रहे, इन खिलाडियों का उद्योग मंत्री कवासी लखमा, सांसद श्री दीपक बैज,संसदीय सचिव श्री रेखचन्द जैन, चित्रकोट विधायक श्री राजमन बेंजाम द्वारा जिला कार्यालय के प्रेरणा सभाकक्ष में सम्मानित किया गया। इस अवसर पर नगर निगम सभापति श्रीमती कविता साहू, इंद्रावती बेसिन विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष श्री राजीव शर्मा,कलेक्टर श्री विजय दयाराम के., सी ई ओ जिला पंचायत श्री प्रकाश सर्वे सहित अन्य अतिथियों ने खिलाड़ियों को प्रोत्साहित किए। मंत्री श्री लखमा ने खिलाडियों को प्रोत्साहित करते हुए कहा कि खूब खेलो, अच्छा खेलो, देश-प्रदेश के साथ-साथ क्षेत्र का नाम रोशन करो।

ज्ञात हो कि भारत सरकार द्वारा आयोजित पहली खेलो इंडिया के तहत आदिवासी नेशनल टूर्नामेंट

भुनेश्वर उड़ीसा में छत्तीसगढ़ राज्य की फुटबॉल टीम ने स्वर्ण पदक जीता, टीम में बस्तर की 8 बालिका खेल रही थी, फाइनल मैच में बस्तर की मुस्कान, अर्पिता ने गोल मारा। एथलेटिक्स में 5 हजार मीटर दौड़ में प्रमिला मांडवी रजत पदक प्राप्त किया। खो खो में छत्तीसगढ़ टीम ने कांस्य पदक प्राप्त किया टीम में बस्तर दो खिलाड़ी ममता कश्यप और ममता मांडवी शामिल थे। कबड्डी में छत्तीसगढ़ की टीम ने कांस्य पदक जीता, टीम में बस्तर से एक खिलाड़ी गीता मंडावी शामिल थे। हॉकी प्रशिक्षण केंद्र पंडरीपानी के 5 बालक और 5 बालिका ने राज्य के टीम की ओर से भाग लिया टीम ने क्वार्टर फाइनल तक खेले।

छत्तीसगढ़ में नशामुक्ति के लिए चलेगा जनजागरण अभियान, सीएम ने दिए निर्देश

■ **विधानसभा चुनाव से पहले बड़ा दांव**

रायपुर। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव 2023 से पहले भूपेश सरकार ने एक बार फिर बड़ा दांव खेला है। प्रदेश में शराबबंदी की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। सीएम भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ में नशामुक्ति के लिए व्यापक जन-जागरण अभियान शुरू करने के दिए निर्देश दिए हैं। इस संबंध में मुख्य सचिव को निर्देश दिए हैं।

आदेश में कहा गया है कि समाज कल्याण विभाग एक महीने के भीतर नशामुक्ति जन-जागरण अभियान को लेकर कार्ययोजना की ब्लू प्रिंट तैयारी करे। अभियान को लेकर नशामुक्ति के क्षेत्र में कार्य कर रहे फेमस व्यक्तियों और संस्थाओं से परामर्श लिया जाए। इसके साथ ही

एनजीओ, सामाजिक, सांस्कृतिक और धार्मिक संस्थाओं का भी सहयोग लिया जाए। विद्यार्थियों में जन जागरूकता के लिए शैक्षणिक संस्थाओं में सेमीनार आयोजित कराए जाए। ताकि छात्रों के साथ ही युवा पीढ़ि को भी जागरूक किया जा सके।

मुख्यमंत्री ने मुख्य सचिव को जारी निर्देश में कहा कि

नशा एक ऐसी गंभीर सामाजिक बुराई है, जिससे मनुष्य का अनमोल जीवन गंभीर बीमारियों से ग्रस्त हो जाता है। वह अकाल मृत्यु का शिकार हो जाता है। नशे के लिए लोग गांजा, भांग, जर्दा गुड़ाखू, तंबाकू, शराब, गुटखा, धूम्रपान, चरस, अफीम, स्मैक, कोकीन और ब्राउन शुगर जैसे मादक पदार्थों का सेवन करते हैं। छत्तीसगढ़ पुलिस इसे लेकर लगातार कार्रवाई कर रही है। छत्तीसगढ़ सरकार भी इसे रोकने का प्रयास कर रही है, लेकिन जब तक हम इस अभियान को जनमानस से नहीं जोड़ेंगे और जन-जन तक नहीं पहुंचायेंगे, तब तक यह अभियान सफल नहीं हो सकता। युवा पीढ़ी में नशे की प्रवृत्ति तेजी से बढ़ना अत्यधिक चिंताजनक विषय है।

निर्देश में आगे कहा है कि समाज को नशे के दुष्प्रभावों से बचाने, युवा पीढ़ी को बर्बादी से बचाने तथा उनकी संपूर्ण ऊर्जा का राष्ट्र निर्माण में उपयोग करने के लिए जरूरी है कि नशा मुक्ति के लिए बड़ा जन-जागरण अभियान शुरू किया जाए। उच्चतर माध्यमिक शालाओं, महाविद्यालयों एवं विश्वविद्यालयों के छात्रों में जागरूकता के लिए सेमीनार आयोजन किए जाए। शासकीय प्रयासों के साथ ही एनजीओ सामाजिक, सांस्कृतिक और धार्मिक संस्थाओं से भी सहयोग लिया जाए।

भाजपा को बड़ा झटका

भूपेश सरकार के इस प्रयास से बीजेपी के लिए एक बड़ा झटका भी माना जा रहा है। क्योंकि बीजेपी प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने के साथ ही लगातार शराबबंदी की मांग को लेकर आवाज बुलंद करती रही है। लगातार राज्य सरकार को घेरती रही है। विधानसभा चुनाव 2018 के दौरान कांग्रेस के घोषणा पत्र में शराबबंदी के वादे को लेकर भूपेश सरकार पर निशाना साधती रही है। बीजेपी राज्य सरकार को शराबबंदी करने के लिए कटघरे में खड़ा करती रही है। बता दें कि विधानसभा चुनाव 2018 के दौरान कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में प्रदेश में शराबबंदी करने का वादा किया था।

ऐसे होगा नशामुक्ति के लिए प्रयास

समाज कल्याण विभाग एक महीने के भीतर नशामुक्ति जन-जागरण अभियान को लेकर कार्ययोजना की ब्लू प्रिंट तैयारी करेगा। नशामुक्ति के क्षेत्र में कार्य कर रहे फेमस व्यक्तियों और संस्थाओं से परामर्श लिया जाए। एनजीओ, सामाजिक, सांस्कृतिक और धार्मिक संस्थाओं का सहयोग लिया जाएगा। छात्रों में जन जागरूकता के लिए शैक्षणिक संस्थाओं में सेमिनार होंगे। छात्रों के साथ ही युवा पीढ़ी को जागरूक किया जाएगा।

सिंहदेव के बयान पर पूर्व सीएम

कल क्या होगा, कहा नहीं जा सकता, पहले उन्होंने मानसिकता बना ली थी: रमन

राजनांदगांव। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नौ साल का कार्यकाल पूरा होने के अवसर पर भाजपा गरीब कल्याण सेवा सुशासन के अंतर्गत महाजनसंपर्क अभियान चला रही है। इसे लेकर अलग-अलग तरह के आयोजन पार्टी की ओर से हो रहे हैं। इसी के तहत राजनांदगांव में भी भाजपा व्यापार प्रकोष्ठ ने लोकसभा स्तरीय सम्मेलन आयोजित किया था।

डॉ. रमन सिंह ने स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव के भाजपा में शामिल होने के मामले को लेकर चुटकी ली। रमन सिंह ने कहा कि, पहले उन्होंने मानसिकता बना ली थी। अब कांग्रेस नहीं छोड़ूंगा बोल रहे हैं। आज की स्थिति में उनकी मानसिकता क्या है और कल क्या होगी, कहा नहीं जा सकता। पूर्व सीएम गुरुवार को भाजपा व्यापार प्रकोष्ठ के लोकसभा स्तरीय सम्मेलन में शामिल होने के लिए राजनांदगांव पहुंचे थे। एक दिन पहले ही सिंहदेव ने कहा था कि, विपक्ष के कई नेताओं ने संपर्क किया, लेकिन वह कांग्रेस छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। शहर के सिंधु भवन में भाजपा व्यापारी प्रकोष्ठ के महासम्मेलन में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉ रमन सिंह ने शिरकत की। इस दौरान व्यापारियों ने रमन सिंह के सामने अपनी व्यापार से जुड़ी बातें और समस्याओं से अवगत कराया। साथ ही इस दिशा में केंद्र शासन द्वारा बेहतर योजना बनाए जाने को लेकर आग्रह किया। डॉ रमन सिंह ने कहा कि व्यापार का असर राज्य की अर्थव्यवस्था पर सीधा पड़ता है। जैसे-जैसे व्यापार,व्यवसाय बढ़ेगा तो छत्तीसगढ़ का जीडीपी बढ़ेगा। वहीं प्रति व्यक्ति आय बढ़ेगी,जिससे लोगों की क्रय शक्ति बढ़ेगी और इससे व्यापार बढ़ेगा।

अघोषित बिजली कटौती पर तीखा हमला

बिजली सरप्लस स्टेट को कांग्रेस ने अंधेरे युग में धकेल दिया : बृजमोहन

रायपुर। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ विधायक व पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने प्रदेशभर में हो रही लगातार अघोषित बिजली कटौती को लेकर प्रदेश की कांग्रेस सरकार पर तीखा हमला बोला है। श्री अग्रवाल ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों के साथ-साथ अब शहरों में सैकड़ों बार हो रही अघोषित बिजली कटौती से प्रदेश सरकार का नाकारापन सामने आ गया है।

बिजली विभाग के स्टेटस ऑफ टेक्नीकल कम्पलेंट्स में दर्ज शिकायतें इस बात की तस्दीक कर रही हैं कि प्रदेश सरकार ने छत्तीसगढ़ को अंधकार-युग में धकेल दिया है। अकेले बिलासपुर शहर में एक दिन में 323 बार बिजली आपूर्ति बंद हो रही है। सिटी सर्किल में दो माह में 19,423 शिकायतें दर्ज हुई हैं। ऊर्जाधानी कहे जाने वाले कोरबा में तो हालात और बदतर हैं जहां हर रोज बिजली बंद होने की 155 शिकायतें दर्ज हो रही हैं। श्री अग्रवाल ने कहा कि जब शहरी क्षेत्रों में बिजली कटौती का यह आलम है, तो ग्रामीण इलाकों की हालत क्या होगी, यह सहज अनुमान लगाया जा सकता है। पूरे प्रदेश में बिजली कटौती से हर वर्ग त्रस्त है और प्रदेश की कांग्रेस सरकार को घोटाले, भाष्टाचार करके तिजोरियां भरने से फुर्सत नहीं है।भाजपा विधायक व पूर्व मंत्री श्री अग्रवाल ने कहा कि प्रदेश सरकार ने छत्तीसगढ़ का हर मामले में बेड़ा गर्क कर रखा है। बिजली कटौती के चलते अस्पतालों में इलाज करा रहे बच्चों की मौतों का कलंक तक प्रदेश को शर्मसार कर चुका है, लेकिन प्रदेश सरकार की संवेदनहीनता अपनी जगह कायम रही है। श्री अग्रवाल ने कहा कि बिजली बिल हाफ करने का वादा करके सत्ता में आई कांग्रेस सरकार ने पूरी बिजली ही साफ कर रखी है। प्रदेश की पूर्ववर्ती भाजपा सरकार ने जिस मनोयोग से छत्तीसगढ़ को बिजली के मामले में सरप्लस स्टेट बनाकर जीरो पॉवर कट की आदर्श व्यवस्था स्थापित की थी और अपनी जरूरत की बिजली का उपयोग करके अन्य राज्यों को बिजली की आपूर्ति की थी, उस समूची व्यवस्था को कांग्रेस की भूपेश सरकार ने तहस-नहस करके रख दिया है। श्री अग्रवाल ने कहा कि बिजली कटौती को लेकर जब भी सरकार के खिलाफ आवाज उठी तो सरकार ने राजद्रोह जैसे आरोप में गिरफ्तारियां करके अपने अहंकार और आतंक का पोषण किया है। यह भी जाँच का विषय है कि बार-बार की इस बिजली कटौती का कहीं किसी घोटाले और कमीशनखोरी से कनेक्शन तो नहीं है? प्रदेश में अनाप-शनाप बिजली दरें बढ़ाकर और उसी तर्ज पर बिजली बिलों का वितरण करके भी बिजली बिल हाफ के नाम पर प्रदेश के बिजली उपभोक्ताओं से धोखाधड़ी कर रही है।

कांग्रेस के आरोप पर पलटवार

तथ्यहीन आरोप लगाने से कांग्रेस की विश्वसनीयता खत्म: ओपी चौधरी

रायपुर। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश महामंत्री ओ.पी. चौधरी ने प्रदेश की पूर्ववर्ती भाजपा सरकार के कार्यकाल में 1 लाख करोड़ के घोटाले हेने के कांग्रेस के आरोप पर पलटवार कर कहा है कि अगर ऐसा कोई घोटाला हुआ था तो पिछले साढ़े चार वर्षों से सत्ता में बैठी कांग्रेस की सरकार को जांच कराने से किसने रोका? श्री चौधरी ने कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव में अपनी हार देखकर कांग्रेसी इतने बदहवास हो गए हैं कि मनमाने आँकड़ों के साथ ऊलजुलूल आरोप लगाने में उनकी अब राहुल गांधी से भी आगे निकलने की होड़ मची हुई है!

भाजपा प्रदेश महामंत्री श्री चौधरी ने कहा कि कांग्रेस के लोग तथ्यहीन और निराधार आरोप लगाकर अपने घोटालों और भ्रष्टाचार से प्रदेश की जनता का ध्यान भटकाने की लाख कोशिश करके भी सफल नहीं होंगे। जब से प्रदेश में कांग्रेस सत्तारूढ़ हुई है, राजनीतिक विरोधियों के खिलाफ उसने बदलापुर की राजनीति का एजेंडा चला रखा था। इसके लिए पचासों एसआईटी बनाकर चरित्र हनन की राजनीत तक की लेकिन पूर्ववर्ती भाजपा सरकार के विरुद्ध एक रुपए तक का घोटाला अब तक साबित नहीं कर पाई, उल्टे हर बार कांग्रेस को मुंह की खानी बड़ी। शराब, रेत, कोयला, राशन और केन्द्र के मुफ्त चावल आदि में हजारों करोड़ रुपए के घोटालों के दलदल में धँसी कांग्रेस की प्रदेश सरकार का बचाव करते कांग्रेस संचार प्रमुख को अपने नाम के अनुरूप अच्छे शील का परिचय देकर तथ्यों पर बात करनी चाहिए, लेकिन वे ऊलजलूल नित-नए आँकड़े लाकर निराधार आरोप लगाकर प्रदेश को गुमराह करने में लगे हुए हैं।

महामंत्री ओपी चौधरी ने कहा कि कांग्रेस नेता ज़रा प्रदेश को यह तो बताएँ कि ये नित-नए आँकड़े वे लाते कहां से हैं? क्या इन आंकड़ों के प्रेरणास्रोत राहुल गांधी हैं, जो खुद जमानत पर हैं।

भाजपा प्रदेश महामंत्री श्री चौधरी ने कहा कि कांग्रेस सत्ता में रहकर आरोपों लगाने की ओछे स्तर की राजनीति करने पर उतर आई है। कांग्रेस अब तक अपने एक भी आरोप को साबित नहीं कर पाई जबकि कांग्रेस सरकार और उनके नेता व दलाल इस कदर घोटालों में उलझकर जेल की हवा खा रहे हैं और न्यायालय तक से उन्हें जमानत नहीं मिल पा रही है। भाजपा की पूर्ववर्ती सरकार पर घोटालों का थोथा आरोप लगाने के बजाय उसकी जांच कराकर प्रमाणित करना कांग्रेस की सरकार का जिम्मा था। श्री चौधरी ने कहा कि सत्ता में कांग्रेस है, लेकिन लगता है कि कांग्रेस के लोग भूल गए हैं।

रंजन को रंजना की खुली चुनौती...

रायपुर। छत्तीसगढ़ भाजपा प्रदेश प्रवक्ता विधायक रंजना साहू ने कांग्रेस की राज्यसभा सांसद रंजीत रंजन द्वारा प्रदेश में दोबारा कांग्रेस की सरकार बनने पर पांच सौ रुपये में रसोई गैस सिलेंडर देने के वादे पर कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि कांग्रेस का पिछला घोषणा पत्र तैयार करने वाले टीएस सिंहदेव तो वादे पूरे न होने के कारण चुनाव लड़ने की हिम्मत नहीं कर पा रहे और अब कांग्रेस की राज्यसभा सांसद छत्तीसगढ़ में नई घोषणावीर बन कर सामने आई है। वे कह रही हैं कि उनका वादा चुनाव घोषणा पत्र में शामिल होगा। लगता है कि सिंहदेव जी द्वारा हाथ जोड़ लेने के कारण मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने रंजीत रंजन को कांग्रेस का नया झांसा पत्र तैयार करने का ठेका दे दिया है।भाजपा प्रदेश प्रवक्ता विधायक रंजना साहू ने कहा कि पिछले चुनाव में कांग्रेस ने महतारी सम्मान योजना के तहत सभी महिलाओं को 500 रुपये प्रति माह देने का वादा किया था। ग्रामीण परिवारों को साल में चार गैस सिलेंडर मुफ्त देने का वादा भी कांग्रेस के घोषणा पत्र में शामिल था। उन्होंने कहा कि मैं छत्तीसगढ़ की बेटी, बिहार की बेटी को खुली चुनौती देती हूं कि मुख्यमंत्री से पूछें कि ग्रामीण परिवारों को क्या यह सालाना 4 गैस सिलेंडर दिए हैं, नहीं दिए हैं तो यह किसको दे दिए? कहां बेच दिए? रंजीत रंजन मुख्यमंत्री से पूछें कि महतारी सम्मान योजना के हर माह 5 सौ रुपए साढ़े चार साल से क्या सोनिया महतारी को समर्पित कर रहे हैं, क्योंकि छत्तीसगढ़ की महतारियों को तो यह राशि मिल नहीं रही। महिलाओं का कर्ज माफ क्यों नहीं किया गया।

छत्तीसगढ़ में मीडिया पर आपातकाल, सरकार संरक्षित रेत माफिया भी ढाने लगे कहर: केदार

रायपुर। छत्तीसगढ़ भाजपा प्रदेश महामंत्री केदार कश्यप ने कोंडागांव जिले के फरसगांव जो कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम का गृह क्षेत्र है में रेत माफिया द्वारा अवैध रेत उत्खनन की हकीकत सामने ला रहे पत्रकारों पर हमले और उनके वाहनों में तोड़फोड़ की वारदात को कांग्रेस की भूपेश बघेल सरकार के संरक्षण में हुआ मीडिया पर हमला करार देते हुए कहा कि भूपेश बघेल के राज में मीडिया पर अघोषित आपातकाल लागू है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की सरकार की करतूतें सामने लाने वाले पत्रकारों का दमन हो रहा है। उनके परिवारों का मानसिक उत्पीड़न हो रहा है। सरकार के संरक्षण में हो रहे घपले घोटाले की जानकारी जनता तक पहुंचाने वाले पत्रकारों के खिलाफ षड्यंत्र करके उन्हें जेल में ठूंसा जा रहा है। सुनील नामदेव, नीलेश शर्मा, कोंडागांव के पत्रकारों सहित प्रदेश भर में कई पत्रकार सरकार और उसके पालतू माफिया के शिकार हुए हैं।भाजपा प्रदेश महामंत्री केदार कश्यप ने कहा कि पूरे छत्तीसगढ़ में सरकार के पैदा किये और पाले पोसे माफिया को छत्तीसगढ़ की सम्पदा लूटने की छूट मिली है। सरकार के संरक्षण में कोल माफिया, शराब माफिया और रेत माफिया सक्रिय हैं। इनके खिलाफ सरकार के संबंधित विभाग कोई कार्रवाई नहीं करते क्योंकि उनके हाथ कांग्रेस सरकार ने बांध रखे हैं। जब चौथा स्तंभ अपने दायित्वों का निर्वहन करते हुए भूपेश बघेल सरकार के अंधेर नगरी चौपट राज की हकीकत सामने लाते हैं तो उन पर भूपेश बघेल की पुलिस और भूपेश बघेल सरकार के संरक्षित माफिया का कहर टूट पड़ता है।

काम एक धेले का नहीं, नाम बदलने का ठेका ले रखी है कांग्रेस: संजय श्रीवास्तव

रायपुर। छत्तीसगढ़ प्रदेश भाजपा के वरिष्ठ नेता और रायपुर नगर निगम के पूर्व सभापति संजय श्रीवास्तव ने राजधानी के वीआईपी रोड का नाम बदलकर 'राजीव गांधी मार्ग' किये जाने पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि ऐसी चाटुकारिता के अलावा कांग्रेस से और कोई उम्मीद रायपुर की जनता कर भी नहीं सकती। चार साल में एक गली तक नहीं बनवाने वाले महापौर अपने मुख्यमंत्री के नक्शेकदम पर चल रहे हैं। बल्कि बड़े मियां तो बड़े मियां, छोटे मियां सुभानअल्ला साबित हो रहे हैं। जिनकी सियासी सरपरस्ती में 2 हजार करोड़ का शराब घोटाला संभव है, जिनके इशारे पर शहर भर में कब्जेदारी चल रही है, स्मार्ट सिटी के पैसों का दुरुपयोग कर भारी भ्रष्टाचार चल रहा है, वे केवल नाम बदल सकते हैं। घोटालेबाजी के अलावा काम कुछ नहीं कर सकते। उन्होंने कहा कि अभी कुछ माह पहले जब बिना टेंडर के तेलीबांधा से वीआईपी रोड चौक के डिवाइडर पर कलाकारी हो रही थी, तभी संकेत मिल गए थे कि इसके बाद एक और कलाकारी होने वाली है।

भाजपा नेता श्रीवास्तव ने कहा कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने साढ़े चार साल में यदि कोई काम किया है तो वह केवल नाम परिवर्तन और नाम से छेड़छाड़ करने का काम किया है। उन्होंने तो राज्य निर्माता अटलजी के नाम पर विकसित नई राजधानी के नाम से छेड़छाड़ करने तक की निर्लज्जता दिखाई। दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम का नाम बदलने की कोशिश की, कुशाभाऊ ठाकरे यूनिवर्सिटी का नाम उन्हें चुभता है।

छत्तीसगढ़/राजधानी
प्रमुख समाचार

भाजपा नेता मणिपुर हिंसा पर खामोश क्यों: मरकाम

रायपुर। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम ने कहा कि मोदी सरकार और भाजपा अपने चुनावी लाभ के लिये देश द्रोहियों के साथ खड़ी होने में परहेज नहीं करती है। यूनाइटेड कुकी लिबरेशन फ्रंट प्रमुख के सनसनीखेज खुलासे से सामने आया है कि भाजपा ने मणिपुर में चुनाव जीतने के लिए देश विरोधी ताकतों का सहारा लिया था। देश के प्रति भाजपा की कथनी और करनी में हमेशा ही फर्क रहा है। खुद को देशभक्त बताने वाले भाजपा के नेता मणिपुर हिंसा पर खामोश हैं और देश विरोधी ताकतों के साथ हैं। यूकेएलएफ के प्रमुख एसएस हाओकिप द्वारा किए गए खुलासे की जांच राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) से कराने और असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा व भाजपा नेता राम माधव पर एनएसए (राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम) के तहत मामला दर्ज किया जाये।प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम ने कहा कि यूकेएलएफ सुप्रीमो द्वारा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को लिखे गए पत्र का उल्लेख किया है, जिसमें यूकेएलएफ नेता ने सनसनीखेज खुलासा किया है कि असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा और भाजपा के वरिष्ठ नेता राम माधव ने उनके साथ एक समझौता किया था। इस समझौते के तहत उन्होंने और उनके संगठन ने 2017 व 2022 के दो विधानसभा चुनावों और 2019 के लोकसभा चुनाव में भाजपा का समर्थन किया था।

15 से 17 जून तक मुंबई में होगा ''राष्ट्रीय विधायक सम्मेलन''

रायपुर। छत्तीसगढ़ विधान सभा अध्यक्ष मान. डॉ. चरणदास महंत ने मुंबई में 15 से 17 जून, 2023 तक आयोजित भारत के पहले ''राष्ट्रीय विधायक सम्मेलन'' में पहले दिन हिस्सा लिया । नवीन भारत के निर्माण, विकास की परिकल्पना को राजनीति के माध्यम से सफल और साकार करनें के उद्देश्य से, एमआईटी के तत्वाधान में भारतीय विधायक सम्मेलन का देश में प्रथम बार आयोजन, मुम्बई में किया गया है। दिनांक 15 जून को सम्मलेन के परिचयात्मक बैठक में देश के समस्त विधान मंडल के माननीय अध्यक्षो का स्वागत करते हुए सम्मेलन के उद्देश्यों से अवगत कराया गया तथा आने वाले 3 दिनों में होने वाले बैठकों की जानकारी देते हुए पूरे दिवसों में सभी की उपस्थिति के लिए निवेदन किया गया।इसके अलावा इस बैठक में मान. अध्यक्ष छत्तीसगढ़ विधान सभा डॉ. चरणदास महंत ने अपने सम्बोधन में देश के समस्त मान. अध्यक्षों से आव्हान किया कि वे समस्त एक मंच पर आते हुए देश के विकास में अग्रसर हों। उक्त सम्मेलन के दौरान जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर मुंबई में आयोजित द्वितीय सत्र में देश की विधानसभा/विधान परिषद के मान. अध्यक्ष/सभापति, मान. उपाध्यक्ष/ मान. उपसभापति, मान. विधायकगण एवं समस्त विधान मंडलों/ विधान परिषदों के मान. सचिव एवं सूचना/ मीडिया अधिकारी सम्मिलित हुए ।

बेटियों को धमकाओ, बृजभूषण को बचाओ : शुक्ला

रायपुर। दिल्ली पुलिस द्वारा सांसद बृजभूषण शरण खिलाफ दायर पास्को एक्ट की जांच पर क्लोजर रिपोर्ट लगाने तथा केस वापस लेने को कांग्रेस ने दुर्भाग्यजनक बताया है। प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि बेटी बचाओ का फर्जी नारा गढ़ने वाली मोदी सरकार का असली मकसद अपराधी बचाओ है। एक नाबालिग पहलवान लड़की ने बाहुबली बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण के खिलाफ पास्को की शिकायत दर्ज कराई, लेकिन मोदी सरकार की दिल्ली पुलिस ने एफआईआर तब दर्ज की जब सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई। अपराधी को तत्काल अरेस्ट करने की जगह पुलिस, सरकार के मंत्री सब एड़ी चोटी का जोर लगा देते हैं उस बेटी को झूठा साबित करने के लिए। नियम के अनुसार पास्को की शिकायत पर आरोपी को तुरंत हिरासत में लिया जाता है। लेकिन बृजभूषण शरण सिंह सरेआम घूम रहा था, दबाव बना रहा था, मीडिया को इंटरव्यू दे रहा था, ओलंपिक मेडल की कीमत 15 रुपए बता रहा था, गुड टच-बैड टच पर ज्ञान दे रहा था, लोकसभा चुनाव लड़ने की दावेदारी ठोंक रहा था।प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि सोचिए, 10 मई को नाबालिग बच्ची ने शिकायत दर्ज कराई।

आदिवासी पुरखौती सम्मान यात्रा का हुआ समापन

रायपुर। भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जनजाति मोर्चा द्वारा निकाली गई पुरखौती सम्मान यात्रा रायपुर के जयस्तंभ चौक पर विराम हुई। इस यात्रा की शुरुआत 9 जून से की गई थी शहीद वीर नारायण सिंह की जन्म स्थली सोनाखान जिला बलौदा बाजार से निकलकर यह यात्रा प्रदेश अनुसूचित जनजाति मोर्चा अध्यक्ष विकास मरकाम के नेतृत्व में रायपुर संभाग के सभी जिलों से गुजरी। यह यात्रा बलौदा बाजार, महासमुंद, गरियाबंद, धमतरी दुर्ग और रायपुर जिलों में निकाली गई।आदिवासी पुरखौती सम्मान यात्रा छत्तीसगढ़ के पांच आदिवासी महापुरुषों के जन्मस्थली से निकलकर जिला मुख्यालयों तक पहुंची। अजजा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष ने जानकारी देते हुए कहा कि यह यात्रा राजनीतिक यात्रा नहीं थी बल्कि एक सामाजिक यात्रा थी जिसमें छत्तीसगढ़ के आदिवासी महापुरुषों की भारतीय स्वतंत्रता संग्राम, छत्तीसगढ़ के नवनिर्माण में योगदान और आदिवासी संस्कृति परंपरा को संरक्षित करने में योगदानों को जन-जन तक पहुंचाया गया। आदिवासी पुरखौती सम्मान यात्रा के शहीद वीर नारायण सिंह के जन्मस्थली से निकली इस यात्रा का सफल समापन उनके शहादत स्थल जयस्तंभ चौक पर हुई।यात्रा के बारे में कहा कि प्रदेश की सबसे विशाल यात्रा में से एक थी जोकि हमारे आदिवासी पुरखों के योगदानो को याद करते हुए निकाला गया। छत्तीसगढ़ की जनमानस लंबे समय तक इस यात्रा को याद रखेगी और निश्चित रूप से यह यात्रा महान आदिवासी पुरखों के आदर्शों, स्वप्न और छत्तीसगढ़ के प्रगति के प्रति हम सभी को प्रेरित करती रहेगी।

रमन सरकार के दौरान स्वास्थ्य मामले में छत्तीसगढ़ देश में 21 राज्यों से पीछे था

रायपुर। प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने कहा कि भाजपा सांसद विजय बघेल को रमन सरकार के दौरान के लचर स्वास्थ्य व्यवस्था के लिए प्रदेश की जनता से माफी मांगनी चाहिए।रमन सरकार के दौरान स्वास्थ्य के मामले में देश मे छत्तीसगढ़ 21 राज्यों में 20वे नंबर पर था। इस दौरान स्मार्ट कार्ड घोटाला, जहरीली दवाओं से मौत,नशबंदी कांड,आंख फोड़वा कांड, गर्भाशय कांड, जैसे काले कांड हुये। अस्पतालों की दुर्दशा थी। प्रदेश के शासकीय अस्पताल रमन सरकार की उदासीनता के शिकार थे अस्पतालों में विशेषज्ञ चिकित्सक,चिकित्सक, तकनीकी स्टाफ नही थे। रमन सरकार के दौरान 1114 विशेषज्ञ चिकित्सक,410 चिकित्सक, 1512 नर्सिंग स्टाफ पद खाली थे आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र में चिकित्सा अमला उपलब्ध कराने में रमन सरकार अक्षम रही है।पूर्व के रमन सरकार के दौरान के मातृत्व मृत्यु दर में बीते 4 वर्षों में 22 अंकों की गिरावट आई 2016 से 2018 के बीच 159 एमएमआर वाले छत्तीसगढ़ का एमएमआर अब घटकर 137 पर पहुंच गया है प्रदेश में मातृत्व मृत्यु दर का अब तक का यह सबसे न्यूनतम आंकड़ा है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के सरकार के द्वारा स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को मजबूत किया गया।

राज्य के 36 गढ़ कल्चुरी काल के मुख्य प्रशासनिक यूनिट: अलंग

रायपुर। रायपुर संभागायुक्त श्री संजय अलंग आज एनआईटी में एक भारत श्रेष्ठ भारत के तहत आयोजित युवा संगम कार्यकम में शामिल हुए। उन्होने नागालैंड के एनआईटी सहित विभिन्न शिक्षण संस्थान के विद्यार्थियों को छत्तीसगढ़ की सांस्कृतिक-ऐतिहासिक विरासत से परिचित कराते हुए छत्तीसगढ़ के नाम की व्याख्या की। श्री अलंग ने बताया कि छत्तीसगढ का इतिहास गौरवशाली रहा है। यहां कल्चुरी वंश के त्रिपुरी शाखा का आधिपत्य रहा हैं। उन्होने पहले तुम्माण उसके बाद रतनपुर को अपनी राजधानी बनाया। उस समय छत्तीसगढ़ दक्षिणी कोसल के नाम से जाना जाता था, जो कि छोटी-छोटी जमीदारियों में बंटा हुआ था। इसे उन्होंने मांडलिक नाम दिया।

श्री अलंग ने बताया कि कल्चुरी राजाओं ने प्रशासनिक सुव्यवस्था स्थापित करने के लिए अपने आधिपत्य वाले क्षेत्र को विभिन्न प्रशासनिक यूनिट में बांटा जिसे ही गढ़ का नाम दिया जो छत्तीसगढ़ के नाम से प्रचलन में आया। कालान्तर में अंग्रेजों ने इसे तहसील का नाम दिया जो आज भी प्रशासनिक इकाई मानी जाती है। शिवाजी का उल्लेख करते हुए श्री अलंग ने मराठा साम्राज्य के बारे में बताया। छत्तीसगढ़ में कल्चुरियों के बाद भोसले शासक ने शासन किया। मराठा शासको ने अपने सैनिकों को राजस्व वसूली का कार्य दिया। उनके राजस्व का प्रमुख स्रोत टैक्स थे। जिसे सरदेशमुखी और चौथ कहा जाता था। इनके सैन्य अधिकारी जो राजस्व वसूली कर लाते थे। उन्हे मराठा राजाओं के अधिकारी फडवनीस और चिटनीस रिकार्ड रखते थे। संबधित क्षेत्रों से राजस्व वसूली के संगहण के रिकार्ड रखने के दौरन ही शनै:शनै: छत्तीसगढ शब्द प्रचलन में आता गया। श्री अलंग ने नागपुर शहर के संस्थापक बख्तबुलंद तथा मवाल समाज के संबंध में रोचक जानकारी शेयर की। उन्होंने उपस्थित छात्र-छात्राओं को समकालीन समय का उदाहरण देते हुए बताया कि जैसे की आपने बाहुबली फिल्म देखी होगी, उसमें माहिष्मती का जिक्र आता है। संयोग यह है कि कोसल से जुडे ऐतिहासिक वृतांतों में इसके अनेक वर्णन मिलते है। यद्यपि फिल्म में यह काल्पनिक कहानी है।

इस अवसर पर वेटलिफ्टर श्री रूस्तम सारंग ने कहा कि उनका और नार्थईस्ट के राज्यों का करीब संबध रहा है। छत्तीसगढ में एक मई बोरे बासी दिवस के रूप में मनाया जाता है।

खाद-बीज के अमानक नमूनों के लॉट के विक्रय पर प्रतिबंध

रायपुर। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने खरीफ सीजन के मद्देनजर किसानों को उनकी डिमांड के अनुरूप मानक स्तर के खाद-बीज की उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा है कि खरीफ सीजन की शुरूआत हो चुकी है। किसानों को बेहतर क्वालिटी का खाद और बीज समय मिले, यह सुनिश्चित करना हमारी जिम्मेदारी है। इसमें किसी भी तरह की कमी अथवा लापरवाही नहीं होना चाहिए। मुख्यमंत्री के निर्देश के परिपालन में राज्य के किसानों को मानक स्तर का खाद-बीज और पौध संरक्षण औषधि की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए कृषि विभाग द्वारा विक्रेता संस्थानों से सेम्पल लिए जाने का अभियान तेजी से शुरू कर दिया गया है। कृषि विभाग के जिला स्तरीय अधिकारी अपने-अपने इलाकों में बीज, खाद और कीटनाशक औषधियों के सेम्पल ले रहे हैं, जिसकी जांच गुणवत्ता नियंत्रण प्रयोगशाला में की जा रही है। खरीफ सीजन 2023 में अब तक बीज के 1712, रासायनिक उर्वरकों के 698 तथा पौध संरक्षण औषधियों के 84 सेम्पल एकत्र कर कृषि विभाग के अधिकारियों द्वारा जांच के लिए गुण नियंत्रण प्रयोगशाला को भेजा जा चुका है। कृषि विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार गुण नियंत्रण प्रयोगशाला से प्राप्त रिपोर्ट में बीज के 16, उर्वरक के 14 और पौध संरक्षण औषधि के 3 सेम्पल अमानक पाए गए हैं। अमानक पाए गए सेम्पल के लाट की बिक्री पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगाए जाने के साथ ही संबंधित फर्मों के संचालकों को नोटिस जारी कर जवाब-तलब किया गया है। खरीफ फसलों के बीज के अब तक 1712 सेम्पल लिए गए है, जिसमें से 1518 सेम्पल के विश्लेषण में 1502 सेम्पल मानक स्तर के और 16 अमानक स्तर के पाए गए हैं।

आर.एन.आई.रजि. क्र. CHHHIN/2021/80529, स्वत्वाधिकारी, मुद्रक एवं प्रकाशक- शशांक शर्मा द्वारा मिशन मीडिया प्रा. लि., प्रेस कॉम्प्लेक्स, रजबंधा मैदान, रायपुर (छ.ग.) 492001 से मुद्रित एवं 29/1110, सेवती स्मृति, आजाद चौक, रायपुर (छ.ग.) 492001 से प्रकाशित। संपादक-शशांक शर्मा, मो. 94255-20531.